शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित
राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 13 | अंक : 21 | गुवाहाटी | शनिवार, 22 अगस्त, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

राहुल के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुई एफआईआर पेज 2
विकास की नई रफ्तार के 100 दिन, विकसित असम की दिशा में सरकार... पेज 3
भारत-जापान की युवा पीढ़ी का मिलन, मुख्यमंत्री आवास पर गूंजा दोसी ... पेज 5
दलीप ट्रॉफी फाइनल अब बेंगलुरु की जगह चेन्नई में खेला जाएगा पेज 7

door graphy Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

प्रकृति (सहज) रूप से प्रजा के संपन्न होने से नेता विहीन राज्य भी संचालित होता रहता है।

- आचार्य चाणक्य

प्रधानमंत्री ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के सीईओ और संस्थापकों से किया संवाद

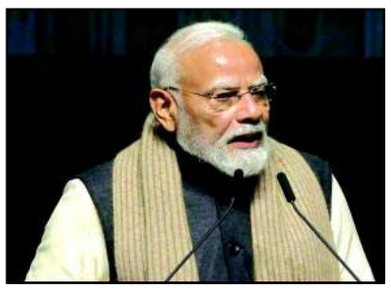

नई दिल्ली (हिंस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सेवा तीर्थ में देश के 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के सीईओ और संस्थापकों के साथ संवाद किया। इस दौरान अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की निजी कंपनियों की बढ़ती क्षमताओं, वैश्विक स्तर पर भारतीय अंतरिक्ष तकनीकों की बढ़ती मांग और अंतरिक्ष क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बैठक में रॉकेट बनाने, दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान, उपग्रह, अंतरिक्ष से जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों, नई तकनीक से रॉकेट इंजन बनाने, अंतरिक्ष एवं रक्षा से जुड़ी जानकारी, अंतरिक्ष में जमा कचरे को हटाने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से स्थानीय मौसम और जलवायु की जानकारी देने वाली तकनीकों पर काम कर रहे स्टार्टअप के प्रमुख शामिल हुए। स्टार्टअप प्रमुखों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को काम करने की अनुमति देने के सरकार के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उद्योग के लिए कई नए अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने बताया कि भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनियों द्वारा विकसित तकनीकों को अपनाने और उनका इस्तेमाल करने में दुनिया के कई देशों की कंपनियां रुचि दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को अपनी तकनीकों के नए उपयोग तलाशने और ऐसी तकनीक विकसित करने पर ध्यान देने को कहा, जिससे आम लोगों का जीवन आसान हो सके। मोदी ने अंतरिक्ष उद्योग -शेष पृष्ठ दो पर

10 से 14 महीने में बाजार में आ सकता है नया भारतीय मोबाइल ब्रांड : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली (हिंस)। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि अगले 10 से 14 महीनों में एक मजबूत भारतीय मोबाइल ब्रांड बाजार में आ सकता है। उन्होंने बताया कि फिलहाल तीन संभावित कंपनियां भारतीय ब्रांड विकसित करने की दिशा में काम कर रही हैं। हालांकि, उन्होंने इन कंपनियों के नाम बताने से इनकार किया। वैष्णव ने नई मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) के शुभारंभ के मौके पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत ने मोबाइल फोन के निर्माण के क्षेत्र में मजबूत आधार तैयार कर लिया है और अब अगला लक्ष्य अपने भारतीय ब्रांड, भारतीय डिजाइन और अपनी तकनीक विकसित करना है। नई योजना एक अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएगी और पांच साल तक चलेगी। इसके लिए 62,500 करोड़ रुपए का -शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

आज राष्ट्रपति भवन में नहीं होगा गार्ड परिवर्तन समारोह

नई दिल्ली (हिंस)। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के औपचारिक स्वागत के पूर्वाभ्यास के कारण राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में इस शनिवार, 22 अगस्त को होने वाला गार्ड परिवर्तन समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। औपचारिक स्वागत समारोह की तैयारियों और पूर्वाभ्यास के चलते शनिवार को गार्ड परिवर्तन समारोह स्थगित रहेगा।

सज्जन कुमार को *रोल मॉडल* बताना कांग्रेस की सिख विरोधी मानसिकता : ढिल्लों

चंडीगढ़ (हिंस)। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने 1984 सिख नरसंहार के आरोपित सज्जन कुमार को कांग्रेसी नेताओं के *रोल मॉडल* कहे जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं का यह बयान पार्टी की सिख विरोधी मानसिकता को एक बार फिर उजागर करता है। ढिल्लों ने कहा कि 1984 के भयावह और दर्दनाक सिख नरसंहार को 42 वर्ष बीत जाने -शेष पृष्ठ दो पर

सिलीगुड़ी में कानूनी प्रदर्शनी का उद्घाटन अमित शाह ने कहा, डर नहीं, *भरोसे की सरकार* का होगा शासन

सिलीगुड़ी (हिंस)। उत्तर बंगाल के प्रवेशद्वार सिलीगुड़ी में नए आपराधिक कानूनों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को विशाल कानूनी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कावाखाली मैदान में *5 स्तंभ : बदली हुई न्याय व्यवस्था* थीम पर आयोजित *न्याय संहिता प्रदर्शनी* का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी 21 से 26 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य पुराने भारतीय दंड संहिता (1860), दंड प्रक्रिया संहिता (1973) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) की जगह लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के प्रमुख प्रावधानों और बदलावों को आम लोगों के सामने -शेष पृष्ठ दो पर

देशभर की जेलों में बंद सिखों की रिहाई की मांग, पंजाब बंद को मिला मिला-जुला समर्थन

आनंदपुर साहिब, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर में निकाला रोष मार्च, कई जगह जबरन बंद कराए बाजार

चंडीगढ़ (हिंस)। देशभर की जेलों में बंद सिखों की रिहाई की मांग को लेकर शुक्रवार को कौमी इंसाफ मोर्चा के बंद के आह्वान को प्रदेश में मिला-जुला समर्थन मिला। राज्य के कई हिस्सों में सात घंटे तक बाजार बंद रहे, लेकिन उद्योगों तथा सरकारी दफ्तरों ने सामान्य की भांति कामकाज हुआ। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में शुक्रवार को निजी स्कूल व शिक्षण संस्थान बंद रहे। सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक बंद का पूरा असर दिखाई दिया। कौमी इंसाफ मोर्चा के सदस्यों ने जगह-जगह रोष मार्च निकाला। खरड़-चंडीगढ़ हाईवे को बंद किया गया था। यहां ड्यूटी पर जाने वाले लोगों की मोर्चा के सदस्यों से बहस भी हुई। मोहाली में निहंगों ने पिज्जा शॉप बंद कराई। इसे साथ अमृतसर, पटियाला और लुधियाना में कौमी इंसाफ मोर्चा के सदस्यों ने खुली दुकानों को बंद करवाया। इससे पटियाला में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। पुलिस मौके पर पहुंची। फरीदकोट में प्रदर्शनकारियों ने आप विधायक डिंपी ढिल्लों की बस को रोक दिया था। बस को रोके जाने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और उसे वापस बस स्टैंड भेज दिया। अमृतसर और मोहाली में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस भी हुई। जालंधर के मकसूदां की सर्विस रोड पर रास्ता रोकने को लेकर जत्थेबंदियों और कार सवार के बीच विवाद हो गया। कार सवार अस्पताल जाने की बात कह रहा था। उसने अस्पताल की रसीद -शेष पृष्ठ दो पर

राहुल गांधी कानून का सम्मान करें अराजकता न फैलाएं : रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली (हिंस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राहुल गांधी के संसद मार्ग थाने के बाहर किए गए विरोध प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला। भाजपा के मुताबिक जिस मामले को लेकर राहुल गांधी धरना दे रहे हैं, उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी है। राहुल गांधी बिना पूर्व अनुमति संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे, जबकि पुलिस पहले स्पष्ट कर चुकी है कि मामले में एफआईआर दर्ज है और जांच जारी है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में गठित -शेष पृष्ठ दो पर

सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने को राहुल दे रहे धरना : नड्डा

नई दिल्ली (हिंस)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी के धरने को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश एक बार फिर राहुल गांधी की *सस्ती और सुर्खियां बटोरने वाली राजनीति* देख रहा है। उनका यह धरना सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए है। जेपी नड्डा ने मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि यह धरना न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए, बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक हताशा और राहुल की मीडिया में बने रहने की कोशिश का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई की घटना का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट पहले ही ले चुका है और एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय -शेष पृष्ठ दो पर

रेवंत रेड्डी की अमेरिकी यात्रा को विदेश मंत्रालय से नहीं मिली मंजूरी

नई दिल्ली (हिंस)। विदेश मंत्रालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अमेरिका की प्रस्तावित यात्रा को पद एवं उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होने के कारण मंजूरी नहीं दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री की यात्रा का मूल्यांकन अन्य गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा की ही तरह राजनीतिक मंजूरी के लिए किया जाता है। प्रस्तावित कार्यक्रम पद और यात्रा के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। इस विशेष मामले में अमेरिका के संबंध में ऐसा नहीं था। ऐसे में उनकी यात्रा को मंजूरी नहीं दी -शेष पृष्ठ दो पर

भारत-नेपाल ने सीमा सुरक्षा, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर दिया जोर

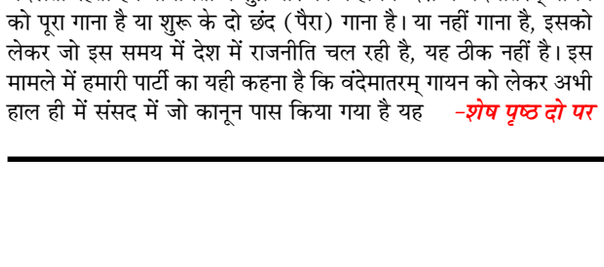

देहरादून (हिंस)। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन एवं सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के साथ-साथ सीमा पार अपराध और आपराधिक गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने पर जोर दिया और सीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और संस्थागत समन्वय बढ़ाने पर भी व्यापक विचार-विमर्श किया। भारत-नेपाल संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 14वीं बैठक 20 और 21 अगस्त को देहरादून में हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की तथा इन क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त -शेष पृष्ठ दो पर

बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि पर तकनीकी स्तर पर चर्चा जारी : विदेश मंत्रालय

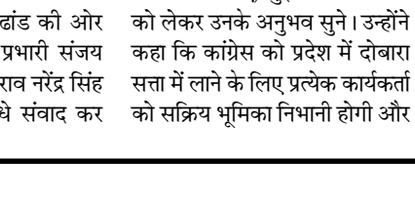

नई दिल्ली (हिंस)। भारत और बांग्लादेश के बीच साल 1996 को हुई गंगा जल संधि अपने 30 वर्ष पूरे करने वाली है और यह इसी साल दिसंबर में समाप्त हो रही है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि गंगा जल संधि पर दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर पर चर्चा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि गंगा जल संधि पर साल 1996 में 30 वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और बांग्लादेश के बीच नदियों से संबंधित सभी मुद्दों पर संयुक्त नदी आयोग के अंतर्गत चर्चा की जाती है। इसके अलावा गंगा जल संधि के अंतर्गत गठित संयुक्त समिति की तकनीकी -शेष पृष्ठ दो पर

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी से की मुलाकात

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान असम से जुड़े शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा नवीकरणीय ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने बैठक को *बहुत उपयोगी* बताते हुए कहा कि बातचीत में असम की शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। उन्होंने असम के प्रति सकारात्मक रुख और निरंतर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि दूसरी बार लगातार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हिमंत विश्व शर्मा पहली बार उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। जोशी ने बताया कि बैठक में असम में समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन को और मजबूत तथा सुव्यवस्थित -शेष पृष्ठ दो पर

वंदे मातरम् : मायावती ने कहा, सरकारें फायदे के लिए बदलती रहती हैं कानून

लखनऊ (हिंस)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने वंदे मातरम् गायन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। जनता का ध्यान बांटने के लिए नई सरकारें अपने फायदे के लिए पुरानी सरकारों के कानूनों को बदलती रहती हैं। मायावती ने शुक्रवार को कहा कि देश में वंदेमातरम् गायन को पूरा गाना है या शुरू के दो छंद (पैरा) गाना है। या नहीं गाना है, इसको लेकर जो इस समय में देश में राजनीति चल रही है, यह ठीक नहीं है। इस मामले में हमारी पार्टी का यही कहना है कि वंदेमातरम् गायन को लेकर अभी हाल ही में संसद में जो कानून पास किया गया है यह -शेष पृष्ठ दो पर

अब सत्ता में नहीं आई तो हरियाणा के भी उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे होंगे हालात : संजय दत्त

कैथल (हिंस)। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैथल में जिला कांग्रेस कार्यकारिणी तथा जिले की चारों विधानसभा सीटों कैथल, कलायत, गुहला और पूंडरी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की संवाद बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, आगामी चुनावी रणनीति तैयार करने और कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर ढांड की ओर से किया गया। प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं, सुझाव और संगठन को लेकर उनके अनुभव सुने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रदेश में दोबारा सत्ता में लाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को सक्रिय भूमिका निभानी होगी और जनता के बीच पार्टी की पकड़ को और मजबूत करना होगा। उन्होंने सवाल किए कि जब जिले में पार्टी चार में से तीन सीटें जीत रही है तो मजबूत स्थिति में ही मानी जाएगी। चौथी पूंडरी की सीट बार-बार हारने के पीछे के कारणों का पता लगाना चाहिए। दूसरी तरफ, जिले के कार्यकर्ताओं ने संगठन पर आरोप लगाए कि पार्टी के लिए काम करने वालों को अनदेखा किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि कांग्रेस पिछले तीन विधानसभा चुनावों से -शेष पृष्ठ दो पर

मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने वित्त मंत्री को बाढ़ राहत कार्यों की जानकारी दी, केंद्र ने सहयोग का दिया भरोसा

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और राज्य में हाल की बाढ़ से हुए नुकसान, राहत एवं पुनर्वास कार्यों तथा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण की तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन की -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
94350-14771

पैलेट से गई आंख की रोशनी, शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे

राहुल के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुई एफआईआर

नई दिल्ली (हिंस)। जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को संसद की ओर निकले प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट लगने से दाहिनी आंख की रोशनी गंवाने वाले छात्र साहिल लोचब की शिकायत पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद साहिल और उसके परिवार की ओर से लगातार की जा रही एफआईआर की मांग पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साहिल ने शिकायत में घटना की जांच के साथ इलाज और मुआवजे की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। साहिल ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान उस पर पांच से छह बार धातु के पैलेट चलाए गए। उसके मुताबिक, वह जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुआ था। वहां से संसद की ओर मार्च के दौरान लाठीचार्ज और आंसू गैस के बीच भगदड़ मच गई। वह भीड़ के साथ पालिका-कनॉट प्लेस इलाके की ओर पहुंचा था। साहिल का दावा है कि इसी दौरान उसके दाहिने हिस्से में छाती, बाजू और आंख के पास कई पैलेट लगे। इसके बाद उसकी आंख, चेहरे, हाथ और छाती से खून निकलने लगा और दाहिनी आंख से दिखाई देना बंद हो गया। शिकायत के मुताबिक, एम्स में हुए सीटी स्कैन में उसके शरीर में 200 से ज्यादा धातु के छर्रे पाए गए। ये छर्रे आंख, गर्दन, छाती, जबड़े और बाजू समेत शरीर के कई हिस्सों में बताए गए हैं। दाहिनी आंख के गड्ढे और उसके पीछे भी छर्रे मौजूद हैं। साहिल के मुताबिक, कुछ छर्रे नस के बेहद करीब होने के कारण निकाले नहीं जा सकते। उसका कहना है कि डॉक्टरों ने बताया है कि आंख के भीतर मौजूद दो छर्रे लंबे समय तक, संभवत: जीवनभर रह सकते हैं। छाती में दिल के पास मौजूद छर्रों को लेकर भी डॉक्टरों ने लंबे इलाज की बात कही है। साहिल के अनुसार, घटना के बाद उसे पहले लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद सफदरजंग अस्पताल और फिर एम्स भेजा गया। एम्स के आरपीसी आई सेंटर और ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज हुआ। 22 जुलाई को आंख की पहली सर्जरी की गई। बाद में एक अगस्त को दूसरी सर्जरी हुई। शिकायत के मुताबिक, दोनों सर्जरी के बाद भी दाहिनी आंख की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने आंख की रोशनी वापस आने की संभावना बेहद कम बताई है। साहिल ने कहा है कि उसका इलाज लंबा चलेगा और शरीर में मौजूद छर्रों के कारण आगे भी उपचार की जरूरत पड़ेगी। साहिल ने शिकायत में कहा है कि घटना के चार सप्ताह से अधिक समय बीतने के बावजूद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। उसने अब पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। साहिल ने जांच के लिए 20 जुलाई की घटनाओं से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखने का अनुरोध किया है। इसमें जंतर-मंतर, संसद मार्ग, कनॉट प्लेस के अंदर-बाहर के इलाके, पटेल चौक, राजीव चौक, मेट्रो स्टेशनों और ट्रैफिक पुलिस के सीसीटीवी फुटेज शामिल हैं। उसने उस दिन की ड्रोन फुटेज को भी सुरक्षित कराने की मांग की है। शिकायत में साहिल ने ऑपरेशन के दौरान उसके शरीर से निकाले गए धातु के छर्रों को पुलिस के कब्जे में लेकर उनकी जांच कराने की मांग की है। साथ ही लेडी हार्डिंग अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, और एम्स से जुड़े सभी मेडिकल रिकॉर्ड और एमएससी जांच में शामिल करने का अनुरोध किया है। साहिल ने कहा है कि गंभीर चोट के कारण उसकी पढ़ाई प्रभावित हुई है और भविष्य की योजनाओं पर भी असर पड़ा है। उसने लंबे इलाज को देखते हुए इलाज के खर्च और मुआवजे के लिए भी उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उसने पुलिस को बयान देने और जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच में यह पता लगाना अहम होगा कि साहिल को चोट किस परिस्थिति में लगी, उस समय मौके पर किन सुरक्षा बलों की तैनाती थी, पैलेट चलाए गए थे या नहीं और अगर चलाए गए तो किस दिशा से और किस हथियार से। सीसीटीवी, वीडियो फुटेज, मेडिकल दस्तावेज और बरामद धातु के छर्रों की फोरेंसिक जांच इस मामले में अहम साक्ष्य साबित हो सकती है।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए विशेष त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड तैयार : शाह

सिलीगुड़ी (हिंस)। तीन दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी *चिकन नेक* की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की विशेष बैठक में उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले इस संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र की सुरक्षा केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। अमित शाह ने बताया कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए विशेष *त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड* तैयार किया गया है। इसके तहत चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी स्थित तीन प्रमुख बेस से पूरे कॉरिडोर क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं होने की पुरानी समस्या का भी उल्लेख किया। हालांकि, वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में इस दिशा में सहयोग मिलने पर उन्होंने संतोष जताया। अमित शाह ने क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2027 के बजट में दिल्ली-सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर बनाने की योजना का उल्लेख किया गया है। इससे उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की कनेक्टिविटी को और मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रणनीतिक स्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बढ़ती अहमियत के रूप में देखा जा रहा है।

भारत में पिछले साल 32 करोड़ मोबाइल फोन बने

नई दिल्ली (हिंस)। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि भारत में पिछले वर्ष 32 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण हुआ। मोबाइल फोन का निर्यात भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं की सबसे बड़ी श्रेणी बन गया है। वैष्णव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत में मोबाइल फोन निर्माण की यह यात्रा पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आगे बढ़ी है। आज भारत में इस्तेमाल होने वाले 99 प्रतिशत से अधिक मोबाइल फोन देश में निर्मित हो रहे हैं।

स्कूल में शिक्षकों की कमी पर अभिभावकों का फूटा गुस्सा, तीन दिन का अल्टीमेटम

हिसार (हिंस)। प्राथमिक पाठशाला गैबीपुर में शिक्षकों की भारी कमी के चलते शुक्रवार को अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। यहां 361 विद्यार्थियों पर महज तीन शिक्षक होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे और तालाबंदी की तैयारी शुरू कर दी। अधिकारियों से बातचीत के बाद ग्रामीणों ने फिलहाल तीन दिन का समय देकर तालाबंदी टाल दी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि इस अवधि में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। अभिभावक कमलेश ने कहा कि बच्चे स्कूल दाल-चावल खाने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। खाना तो घर में भी मिल सकता है, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए पर्याप्त शिक्षक जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी से बच्चों का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित हो सकता है। अभिभावक चमेली ने आरोप लगाया कि शिक्षकों की कमी के कारण पांचवीं कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि जो बच्चे खुद पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं, उन्हें ही दूसरे बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया जाता है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अभिभावक दीपक कुमार ने कहा कि डेपुटेशन पर लगाए गए शिक्षकों को हटाए जाने के बाद यह स्थिति बनी है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से स्कूल में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। गांव निवासी विजय कुमार ने कहा कि स्कूल में करीब 14 शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन तीन शिक्षक ही उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। एसएमसी प्रधान ममता ने कहा कि यदि तीन दिन में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हुई तो ग्रामीण अगला कदम उठाएंगे।

असम में बाढ़ से 92 गांवों के 14799 नागरिक अभी भी प्रभावित

गुवाहाटी (हिंस)। असम में बाढ़ से पांच जिलों के 92 गांवों के 14799 नागरिक अभी भी प्रभावित हैं। सामान्य होते नदियों के जलस्तर के बाद बाढ़ प्रभावितों का जीवन भी धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। प्रभावित लोग अपने आवास एवं खेती को फिर से पटरी पर लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य में बाढ़ से हुए जान-माल के नुकसान एवं चलाए जा रहे राहत, पुनर्वास अभियान की विस्तार से जानकारी दी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 20 अगस्त के आंकड़ों के अनुसार अब सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रहीं है। अब तक 106 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट एवं गोलाघाट जिलों में हुआ है। प्रदेश में 3083 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। इस समय राहत शिविरों में 238 लोग आश्रय लिए हुए हैं। राहत वितरण केंद्रों पर 1165 गैर-शिविर निवासी राहत प्राप्त कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों में गुरुवार को राज्य सरकार ने 4 मेडिकल टीमों को तैनात किया। सरकारी अधिकारी क्षति का आकलन करने में जुटे हुए हैं।

चारा घोटाला : लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें

झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को आठ हफ्ते का दिया अल्टीमेटम

रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में चारा घोटाला मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सीबीआई को दस्तावेज हासिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से समय मांगा और बताया कि उसके पास केस से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह आठ सप्ताह के अंदर रजिस्ट्री से सभी दस्तावेज प्राप्त करे। इसके बाद अगली सुनवाई होगी। लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि चारा घोटाले से जुड़े सभी मामले सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष सूचीबद्ध थे। लेकिन सीबीआई की ओर से दस्तावेज नहीं होने का हवाला देते हुए समय देने की मांग की गई। देवर्षि मंडल ने बताया कि सीबीआई ने लालू की सजा बढ़ाने और उनकी जमानत रद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि हाई कोर्ट ने आधी सजा के आधार पर लालू प्रसाद को जमानत की सुविधा प्रदान की है, जो कि गलत है। सजा की अवधि की गणना गलत की गई है, इसलिए उनकी जमानत रद की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को लालू प्रसाद को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। सीबीआई की ओर से यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट में लालू प्रसाद की अपील पर सात साल से सुनवाई लंबित है।

पृष्ठ एक का शेष

प्रधानमंत्री ने 20 अंतरिक्ष ...

और समाज के विकास से जुड़े दूसरे क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में जमा कचरे को हटाने की तकनीक पर काम करने वाली कंपनियां पर्यावरण से जुड़े संगठनों के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। इसी तरह कृषि के लिए अंतरिक्ष तकनीक विकसित करने वाली कंपनियां कृषि विश्वविद्यालयों और सरकारी विभागों के साथ मिलकर किसानों को बेहतर फैसले लेने और उत्पादन बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऐसा माहौल तैयार करे कि जब दुनिया अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में सोचे तो उसकी नजर भारत पर जाए। उन्होंने कहा कि देश का अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया भर की प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र की कंपनियों का सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बच्चों में छोटी उम्र से ही अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा और रुचि पैदा करने में मदद मिलेगी। संवाद में स्काईरूट एयरोस्पेस, अग्निकुल कॉसमॉस, पिक्सेल, ध्रुव स्पेस, गैलेक्सआई, पियरसाइट, बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस, डिगंतरा, सैटश्योर, सुहोरा टेक्नोलॉजीज, मनस्तु स्पेस, एस्ट्रोबेस, टेकमी2स्पेस, व्योमआईसी, कॉसमॉसर्व स्पेस, ऑर्बिटएआईडी एयरोस्पेस, स्काईसर्व (हाइस्पेस), सेरेंडिपिटी स्पेस, वासर लैब्स और मिस्टईओ के प्रमुख एवं संस्थापक शामिल हुए।

10 से 14 महीने में ...

प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि भारतीय मोबाइल ब्रांड तैयार करने के लिए डिजाइन भारत का और संबंधित कंपनी के स्वामित्व वाला होना चाहिए। उत्पाद किसी दूसरे ब्रांड की नकल नहीं होना चाहिए। सरकार भारतीय कंपनियों से ऐसा डिजाइन तैयार करने की उम्मीद कर रही है, जो अपने बाजार वर्ग में दुनिया के बेहतर उत्पादों से मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा कि तीन संभावित कंपनियों को डिजाइन तैयार करने की दिशा में काम करने के लिए कहा गया है। कंपनियों को किफायती, प्रीमियम या अन्य श्रेणियों में से अपना बाजार चुनना होगा। वैष्णव ने कहा कि भारतीय ब्रांड के लिए अपनी तकनीक और बौद्धिक संपदा विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण है और इस मामले में सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को आज औपचारिक रूप से शुरू किया गया। योजना का उद्देश्य मोबाइल फोन उत्पादन का स्तर बढ़ाना, देश में मोबाइल के हिस्सों का निर्माण बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और घरेलू स्तर पर अधिक मूल्यवर्धन करना है। योजना के तहत भारतीय ब्रांडों को वैश्विक बाजार में पहुंच बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के लिए 62,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है और इसका लक्ष्य पांच वर्षों में करीब 39 लाख करोड़ रुपए का संचयी मोबाइल फोन उत्पादन हासिल करना है। इसके अलावा करीब 60,000 नए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत मोबाइल फोन निर्माताओं को पात्र बिक्री पर 2.25 से पांच प्रतिशत तक प्रोत्साहन मिलेगा। भारत में प्रमुख हिस्सों की खरीद बढ़ाने पर अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत और भारतीय डिजाइन तथा अनुसंधान एवं विकास पर भारतीय ब्रांडों को अतिरिक्त तीन प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल मोबाइल फोन की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि भारत में डिजाइन, तकनीक और अपनी बौद्धिक संपदा विकसित करने का मजबूत आधार तैयार करना है। उन्होंने कहा कि भारत अब विदेशी कंपनियों के लिए केवल उत्पादन का केंद्र नहीं रहना चाहता, बल्कि अपने उत्पाद और ब्रांड भी विकसित करना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 12 वर्षों में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करीब 11 गुना और मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा है, जबकि मोबाइल फोन निर्यात में करीब 166 गुना वृद्धि हुई है। कृष्णन ने कहा कि 2014-15 में भारत में बिकने वाले करीब 70 से 75 प्रतिशत मोबाइल फोन आयात किए जाते थे, लेकिन अब भारत मोबाइल फोन का बड़ा निर्यातक बन चुका है। भारत दुनिया में मोबाइल फोन बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और देश में बिकने वाले लगभग सभी मोबाइल फोन भारत में ही बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन पिछले वर्ष भारत से निर्यात होने वाली सबसे बड़ी एकल वस्तु बना। करीब एक दशक पहले स्मार्टफोन भारत की शीर्ष 100 निर्यात वस्तुओं में भी शामिल नहीं था। अब इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की तीसरी सबसे बड़ी श्रेणी बन चुका है। सचिव ने कहा कि मोबाइल फोन विनिर्माण में घरेलू स्तर पर होने वाला मूल्यवर्धन योजना की शुरुआत के समय करीब 15 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर करीब 23 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इसे आगे 35 से 40 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

देशभर की जेलों में ...

दिखाते हुए बताया कि उसकी पत्नी की डायलसिस हो रही है, लेकिन दोनों पक्षों में बहस बढ़ गई। विवाद के दौरान दोनों तरफ से थप्पड़ चले। इसी बीच गुस्साए सिख व्यक्ति ने साथी से बरछा छीनकर हमला करने की कोशिश की। अमृतसर के गोल्डन गेट से लेकर हॉल गेट व अन्य प्रमुख बाजार बंद रहे। दरबार साहिब तथा आसपास की मार्केट भी बंद रही। बंद का समर्थन करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आज अपने सभी दफ्तर तथा शिक्षण संस्थान बंद रखे। अमृतसर में कई जगह प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों तथा आम जनता के बीच बहस भी हुई। चंडीगढ़-लुधियाना हाईवे को 2 बजे तक बंद रखा गया। खरड़-चंडीगढ़ मुख्य मार्ग बंद होने के कारण हिमाचल, जम्मू और पंजाब से आई बसें खरड़ से आगे नहीं बढ़ पाईं। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को आगे जाने दिया। लुधियाना में ज्यादातर बाजार बंद रहे। शहर की प्रमुख मार्केट चौड़ा बाजार में कुछ दुकानें खुली तो पुलिस ने उन्हें बंद करवा दिया। कौमी इंसाफ मोर्चा के समर्थकों ने लाडोवाल टोल प्लाजा के पास नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया, जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा। इसके अलावा दुगरी में नहर वाले पुल पर भी चक्का जाम किया गया। समराला चौक व शहर के कई इलाकों में सिख संगठनों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शहर में ज्यादातर प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहे, जबकि सरकारी स्कूल खुले रहे। पंजाब बंद का पठानकोट में खास असर देखने को नहीं मिला। शहर के सभी मुख्य बाजार सुबह करीब 10 बजे आम दिनों की तरह खुल गए। हालांकि, सरकारी स्कूलों के साथ कुछ निजी स्कूल भी बंद रहे। पठानकोट के बस स्टैंड पर आम दिनों के मुकाबले कम भीड़ नजर आई। पठानकोट-अमृतसर नेशनल हाईवे स्थित लदपालवां टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया। प्रदर्शन के कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पंजाब बंद के चलते हाईवे पर आवाजाही प्रभावित होने से बड़ी संख्या में वाहन फंस गए हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से ट्रैफिक को संभालते हुए वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से भेजा गया। कौमी इंसाफ मोर्चा के आह्वान पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि अकाली दल ने बंदी सिंहों की रिहाई की मांग को लेकर आनंदपुर साहिब शहर में रोष मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और पंजाब की राज्य सरकार पर निशाना साधा। नेताओं ने कहा कि जिन सिख कैदियों ने अपनी सजाएं पूरी कर ली हैं, उन्हें भी आज तक रिहा नहीं किया गया है, जो न्याय और मानवाधिकारों के सिद्धांतों के खिलाफ है।

अमित शाह ने कहा, डर ...

सरल तरीके से रखना है। उद्घाटन के बाद अमित शाह ने प्रदर्शनी के विभिन्न स्टॉल का भी जायजा लिया। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, मंत्री निशीथ प्रमाणिक, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जलपाईगुड़ी, इस्लामपुर और दार्जिलिंग के विभिन्न स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी प्रदर्शनी में लाया गया। खुले मंच से संबोधित करते हुए अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि देशभर में नए न्याय कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई। शाह ने आरोप लगाया कि नए कानून लागू होने से सिंडिकेट, धन उगाही, वसूली और भय का माहौल खत्म हो जाएगा। चुनाव के दौरान भाजपा ने बंगाल की जनता से *डर की नहीं, भरोसे की सरकार* देने का वादा किया था। शाह के मुताबिक, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पद संभालने के बाद जिन शुरुआती फाइलों पर हस्ताक्षर किए, उनमें तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने से संबंधित फाइल भी शामिल थी। अमित शाह ने नए कानूनों में तकनीक के इस्तेमाल को महत्वपूर्ण बदलाव बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में तकनीक आधारित साक्ष्यों का अधिक इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे जांच और न्याय प्रक्रिया को गति मिलेगी। उन्होंने जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर जैसी व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया। शाह के अनुसार, इन प्रावधानों से देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों को शिकायत दर्ज कराने में सुविधा होगी और मामलों को संबंधित थाने तक पहुंचाने की प्रक्रिया आसान होगी। गृह मंत्री ने कहा कि छह वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की जांच और रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने दावा किया कि तकनीक, पारदर्शिता और निर्धारित समयसीमा के आधार पर न्याय व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया जा रहा है। शाह ने यह भी कहा कि नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद तीन वर्ष के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने महिला और बच्चों की सुरक्षा को नए आपराधिक कानूनों की प्रमुख प्राथमिकताओं में बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और मजबूत जांच व्यवस्था के जरिए अपराधों की जांच को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। अपने भाषण में अमित शाह ने राज्य में कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मामलों का उल्लेख करते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी कानून का ...

समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें दो अन्य न्यायाधीश, सीबीआई के पूर्व निदेशक और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गोली चली थी या नहीं, यह भी इसी समिति की जांच का विषय है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी को कानून के शासन का कोई सम्मान नहीं है? क्या वे अपनी मर्जी से कहीं भी जाकर धरना देंगे और अराजकता फैलाएंगे? भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर अराजकता की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह बिना अनुमति या पूर्व सूचना के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने राहुल गांधी को जानकारी दी है कि जिस घटना का वह जिक्र कर रहे हैं, उसमें पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और मामले की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की जांच के लिए एक हाई-पावर्ड कमेटी गठित की है।

सिर्फ मीडिया में ...

उच्चस्तरीय समिति जांच कर रही है। ऐसे में जब देश की सर्वोच्च अदालत मामले की जांच कर रही है, तो राहुल का थाने के बाहर कैमरों के सामने धरना देना न्यायपालिका पर अविश्वास दिखाता है। उन्होंने कहा कि यह पूरा प्रदर्शन केवल सुर्खियों में बने रहने का प्रयास है। नड्डा ने कहा कि यदि इस पूरे घटनाक्रम के समय पर नजर डालें तो साफ होता है कि कांग्रेस इस समय वंदे मातरम् विवाद को लेकर देशभर में आलोचना झेल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय गीत के अपमान और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता द्वारा तिरंगे के आकार का केक काटे जाने के मामले में जनता जवाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि इसी विवाद से ध्यान भटकाने और अपनी *राष्ट्रविरोधी छवि* को छिपाने के लिए राहुल ने यह नया राजनीतिक नाटक रचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है। अब कांग्रेस युवाओं और छात्रों के भविष्य को भी खत्म कर देना चाहती हैं। राहुल को समझ लेना चाहिए कि जनता उनके हिट एंड रन की नीति को समझ चुकी है।

रेवंत रेड्डी की अमेरिकी...

गई। हालांकि उनकी ब्रिटेन यात्रा को मंजूरी मिल चुकी है। तय कार्यक्रम के अनुसार रेवंत रेड्डी *तेलंगाना राइजिंग* प्रतिनिधिमंडल के साथ 20 अगस्त से ब्रिटेन के दौरे पर हैं। उन्हें 23 अगस्त को ब्रिटेन से अमेरिका जाना था, लेकिन अब वह लंदन से सीधे हैदराबाद लौट आएंगे। उनकी अमेरिकी संस्थानों जैसे हार्वर्ड, एमआईटी और अन्य विश्वविद्यालय के साथ वैश्विक शैक्षणिक भागीदारी के तहत समझौता करने की योजना थी। नियमों के मुताबिक, मुख्यमंत्रियों की विदेशी यात्राओं के लिए विदेश मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है। तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री रेड्डी के ब्रिटेन और अमेरिका दौरे को लेकर काफी समय पहले ही केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। हालांकि, विदेश मंत्रालय ने केवल ब्रिटेन यात्रा को मंजूरी दी।

भारत-नेपाल ने ...

सचिव (बीएम-वन) पौसुमी बासु ने किया, जबकि नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद कफ्ले ने किया। बैठक के दौरान सीमा पार से होने वाले अपराधों और अन्य आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, विशेष रूप से एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी), सड़कों और रेलवे नेटवर्क को बेहतर बनाने तथा इनके प्रभावी उपयोग पर विचार-विमर्श किया। अधिकारियों ने सीमा क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने और सीमा स्तंभों के रखरखाव से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत समन्वय और क्षमता विकास को मजबूत करने के उपायों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े मामलों में नियमित संपर्क एवं समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई। अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में निरंतर सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक नेपाल में आयोजित की जाएगी। इसके लिए तिथि दोनों देशों की आपसी सुविधा के अनुसार तय की जाएगी।

बांग्लादेश के साथ गंगा ...

स्तर पर बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश गंगा जल संधि पर गारंटी क्लोज चाहता है। यह क्लोज 1977 की संधि में था लेकिन 1996 की संधि में हटा दिया गया। इसके तहत सूखे मौसम में बांग्लादेश नदी के बहाव में कमी होने पर भी एक न्यूनतम मात्रा में जल चाहता है।

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व...

करने पर विशेष चर्चा हुई। इसके तहत शिक्षकों को निर्बाध वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने एसएनए-स्पर्श व्यवस्था के तहत धनराशि के सुचारू प्रवाह पर भी चर्चा की, ताकि शिक्षकों के वेतन का समय पर भुगतान हो सके और असम में गुणवत्तापूर्ण एवं समान स्कूली शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ। यह मुलाकात असम के विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने वित्त मंत्री...

मौजूदा स्थिति और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही कार्ययोजना से अवगत कराया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों की आजीविका बहाल करने और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी। बैठक के बाद सोशल मीडिया मंच *एक्स* पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने असम की चिंताओं को *पूरे ध्यान और संवेदनशीलता* के साथ सुना। उन्होंने राज्य की आवश्यकताओं पर वित्त मंत्री की सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए आभार व्यक्त किया। सीतारमण ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि भारत सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उनके जीवन को दोबारा पटरी पर लाने के प्रयासों में असम के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब असम सरकार बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के साथ ही पुनर्वास, पुनर्निर्माण और प्रभावित लोगों की आजीविका बहाल करने की दिशा में अगले चरण की तैयारियों में जुटी है। शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट जिले बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं।

अब सत्ता में नहीं आई ...

लगातार हार रही है। निश्चित तौर पर पार्टी में कोई न कोई कमी रही है, जिसे अब पहचानकर दूर करना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि केवल चुनाव के समय सक्रिय होने के बजाय अभी से गांव, वार्ड और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो की लड़ाई है। यदि कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो हरियाणा के भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हालात हो जाएंगे। संजय दत्त ने पूंडरी विधानसभा सीट को लेकर कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से सक्रिय होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिले की कैथल, कलायत और गुहला विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन मजबूत रहा है, लेकिन पूंडरी में पार्टी को लगातार चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा पर साधा निशानाबैठक में कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला ने एसआईआर मुद्दे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोट काटने का षड्यंत्र रच रही है।

वंदे मातरम् : मायावती ने ...

कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्यों में भी सत्ता परिवर्तन के दौरान सभी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ के हिसाब से या फिर अपनी कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए यह सब करती रहती हैं। एक-दूसरे के बने कानूनों को बदलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि इस समय बेरोजगार युवाओं, *जेन-जी, जी-अल्फा* और बाढ़ जैसे अनेक मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। देश व जनहित में समय की सबसे जरूरी मांग यही है।

सज्जन कुमार को रोल ...

के बावजूद पीड़ित परिवारों के जख्म आज भी हरे हैं। ऐसे संवेदनशील समय में नरसंहार के मुख्य आरोपित को *रोल मॉडल* करार देना पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने और उन्हें फिर से कुरेदने का निंदनीय प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की इस सिख विरोधी सोच की जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने का काम किया है।

विकास की नई रफ्तार के 100 दिन, विकसित असम की दिशा में सरकार के अहम कदम : भाजपा

गुवाहाटी (हिंस)। असम में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के मौजूदा कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान सरकार ने विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, कृषि, उद्योग, पर्यटन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। असम प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता जयंत कुमार गोस्वामी ने कहा कि ये 100 दिन केवल समय का आंकड़ा नहीं, बल्कि विकास और परिवर्तन के लिए सरकार के संकल्प और निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक हैं। गोस्वामी ने कहा कि सरकार ने विकास के साथ जनकल्याण, आर्थिक सशक्तीकरण तथा असम की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा को समान प्राथमिकता दी है। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए गए। इनमें छह महीने तक सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक, विदेश यात्राओं के नियमन को सख्त करना, ईंधन खर्च में 20 प्रतिशत की कटौती और सरकारी कामकाज में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना शामिल है। इसी बैठक में समान नागरिक संहिता के मसौदे को भी मंजूरी दी गई। रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में असम में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन लागू करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर मजबूत करने के साथ सरकारी रिक्त पदों को तेजी से भरने के लिए विशेष कार्यबल का गठन किया गया है। युवाओं को रोजगार, करियर मार्गदर्शन, उद्यमिता और नेतृत्व विकास से जोड़ने के उद्देश्य से अलग युवा सशक्तीकरण एवं विकास विभाग गठित किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई गति मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में असम राज्य उच्च शिक्षा परिषद के पुनर्गठन, गुवाहाटी स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बुनियादी ढांचे के लिए भूमि हस्तांतरण तथा निजी विश्वविद्यालयों और स्कूली शिक्षा से जुड़ी नई नीतियों पर काम किया गया है। इन कदमों का उद्देश्य असम को पूर्वोत्तर के प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करना है। चिकित्सा शिक्षा में एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश से संबंधित नए प्रावधान किए गए हैं। मोरान, मटक, कोच-राजबंशी, ताई अहोम और सुतिया समुदायों के साथ-साथ असम के स्थायी निवासी अनाथ विद्यार्थियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार के अनुसार, इन फैसलों से चिकित्सा शिक्षा में सामाजिक न्याय और समान अवसर को बढ़ावा मिलेगा। कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करने, कृषि आय से संबंधित कर राहत देने और कृषि आधारित उद्यमों को मजबूत करने के उपाय किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण आय बढ़ाने और कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति देने में मदद मिलेगी। शहरी विकास के लिए गुवाहाटी सैटेलाइट शहर विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके जरिए गुवाहाटी के आसपास नियोजित तरीके से सैटेलाइट शहर विकसित किए जाएंगे। वहीं, डिब्रूगढ़ को असम के दूसरे राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए डिब्रूगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा निवेश की योजना बनाई गई है। विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास कोष में वृद्धि से विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में कारोबार को सुगम बनाने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, औद्योगिक संबंधों और श्रमिक कल्याण से जुड़े कदम उठाए गए हैं। सरकार के अनुसार, इससे निवेश का माहौल बेहतर होगा, नए उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होंगे। पर्यटन क्षेत्र में असम पर्यटन होमस्टे विकास एवं पंजीकरण ढांचे को मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीण और सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय उद्यमियों, युवाओं और छोटे आतिथ्य कारोबारियों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया है। सौर ऊर्जा खरीद, कार्बन अवशोषण, पर्यावरण अनुकूल विकास और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े उपायों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना है। इसके अलावा बाल संरक्षण, कोचिंग संस्थानों के नियमन, पात्र पिछड़े वर्गों के लिए गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र की सुविधा और विभिन्न समुदायों के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक अवसरों के विस्तार से जुड़े कई कदम उठाए गए हैं। गोस्वामी ने कहा कि सरकार के पहले 100 दिनों के फैसले अधिक समावेशी, समान और सामाजिक रूप से सुरक्षित असम के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य विकसित असम को केवल एक दृष्टिकोण के रूप में नहीं, बल्कि योजनाबद्ध और निरंतर आगे बढ़ने वाली विकास यात्रा के रूप में साकार करना है।

मंत्री दैमारी ने कौशल, रोजगार और उद्यमिता पहलों की समीक्षा की

गुवाहाटी (हिंस)। असम के कौशल, रोजगार और उद्यमिता मंत्री विश्वजीत दैमारी ने शुक्रवार को जनता भवन में विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में राज्यभर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के वरिष्ठ प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक तथा रोजगार कार्यालयों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में रोजगार एवं शिल्पकार प्रशिक्षण निदेशालय, असम कौशल विकास मिशन, असम कौशल विश्वविद्यालय और रोजगार शाखा के कामकाज पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं। इस दौरान पिछले तीन वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले की स्थिति, विधानसभा क्षेत्रों में संस्थानों की उपलब्धता, रोजगार कार्यालयों को जिला युवा कल्याण केंद्रों के रूप में मजबूत करने, मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना तथा करियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन जैसी पहलों पर चर्चा हुई। मंत्री ने पूर्वोत्तर कौशल केंद्रों, मुख्यमंत्री फ्लाइट योजना और विभाग की अन्य प्रमुख पहलों की भी समीक्षा की। उन्होंने जिला स्तर के अधिकारियों से अधिक सक्रिय और परिणामोन्मुखी तरीके से कार्य करने का आह्वान किया। दैमारी ने कहा कि युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास को रोजगार बाजार की बदलती जरूरतों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और रोजगार कार्यालयों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया।

शिवसागर आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों का विधायक के खिलाफ प्रदर्शन

शिवसागर (हिंस)। शिवसागर के जिला आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों ने शुक्रवार को शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि 20 अगस्त को एक बैठक के दौरान गोगोई ने जिला आयुक्त के साथ दुर्व्यवहार किया। कर्मचारियों ने सिर पर काली पट्टी बांधकर काम का बहिष्कार किया और विधायक के कथित व्यवहार के प्रति नाराजगी जताई। कर्मचारियों के जल्द ही बैठक कर आगे की रणनीति तय करने की संभावना है। यह विरोध प्रदर्शन गोगोई द्वारा जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकारी राहत और वित्तीय सहायता मिलने में कथित देरी को लेकर प्रशासन पर नाराजगी जताए जाने के एक दिन बाद हुआ। जिला आयुक्त के साथ चर्चा के दौरान गोगोई ने बाढ़ प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता देने में देरी पर सवाल उठाया और अधिकारियों से प्रभावित लोगों तक राहत राशि समय पर पहुंचाने की मांग की। गोगोई ने कथित तौर पर जिला आयुक्त से कहा कि अधिकारी क्षेत्र से जा सकते हैं, लेकिन प्रभावित लोगों को उनकी सहायता राशि मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन पर मंत्रियों के निर्देशों का अनुसरण करने तक सीमित रहने का आरोप भी लगाया। विधायक ने जिला प्रशासन से बाढ़ प्रभावित लोगों को समय पर सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की अपील की और कहा कि राहत वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों ने गोगोई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके दुर्व्यवहार पर आपत्ति जताई। गोगोई पिछले कुछ सप्ताह से शिवसागर में बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकारी सहायता पहुंचाने में कथित देरी और प्रशासनिक चूक का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं।

अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ कार्रवाई जारी काजीरंगा में टोके गेको बरामद

गुवाहाटी (हिंस)। असम के वन मंत्री जयंत मल्लबरुवा ने शुक्रवार को बताया कि राज्य में अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि बोकाखात रेंज की टीम ने लताबाड़ी में कोहोरा निवासी राहुल कर्मकार को टोके गेको के कथित अवैध व्यापार के मामले में पकड़ा। टोके गेको वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची-1 में संरक्षित प्रजाति है। आरोपित के कब्जे से एक जीवित टोके गेको बरामद किया गया। मामले की आगे जांच की जा रही है। जांच के माध्यम से वन्यजीव की उत्पत्ति का पता लगाने के साथ ही अवैध व्यापार में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

मेघालय में असम के वाहनों पर हमले के विरोध में जोराबाट में प्रदर्शन, एनएच-6 चार घंटे रहा जाम

गुवाहाटी (हिंस)। मेघालय में असम के वाहनों पर कथित हमले के विरोध में गुवाहाटी के बाहरी इलाके जोरबाट में शुक्रवार को भी असम के टूरिस्ट कार चालकों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिला। सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग-6 अवरुद्ध रहने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और हजारों लोग जाम में फंसे रहे। प्रदर्शन के कारण कई यात्रियों की ट्रेन और उड़ानें छूट गईं। वहीं, एंबुलेंस भी घंटों जाम में फंसी रही। प्रदर्शनकारियों ने मेघालय से आने वाले वाहनों को असम में प्रवेश नहीं करने दिया। असम और मेघालय सरकारों की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद मेघालय से आने वाले

असम के वाहनों को प्रदर्शनकारियों ने आवाजाही की अनुमति दे दी। हालांकि, अंतिम सूचना तक मेघालय के अन्य वाहनों को गुवाहाटी की ओर जाने नहीं दिया जा रहा था। दूसरी ओर, मेघालय के बर्नीहाट में असम से आने वाले वाहनों को स्थानीय लोगों द्वारा वापस लौटाए जाने की सूचना है। दोनों राज्यों की सीमा पर जारी गतिरोध के कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि खासी छात्र संघ (केएसयू) की ओर से की गई हिंसक कार्रवाई पर मेघालय सरकार का मौन समर्थन है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से उपद्रवियों का मनोबल बढ़ा है। यातायात अवरोध के कारण दोनों राज्यों के बीच आवागमन प्रभावित होने के साथ मेघालय के पर्यटन उद्योग पर भी असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से विवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि मेघालय की राजधानी शिलांग में 19 अगस्त की देर शाम केएसयू की ओर से आयोजित रैली के दौरान असम के वाहनों में कथित तौर पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी। इसके बाद असम के जोरबाट में लगातार दूसरे दिन मेघालय के वाहनों की आवाजाही रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया।

मेघालय में फंसे असम के लोगों के लिए हेल्पलाइन जारी

गुवाहाटी (हिंस)। मेघालय में मौजूदा स्थिति को देखते हुए असम सरकार ने असम पुलिस के माध्यम से मेघालय में फंसे या आवागमन में कठिनाई का सामना कर रहे असम के लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर सक्रिय किए हैं। परिजन, रिश्तेदार या किसी व्यक्ति को मेघालय में फंसे लोगों अथवा वाहनों की जानकारी होने पर हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना साझा कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति का नाम, संपर्क नंबर, वाहन नंबर, वर्तमान स्थान तथा अन्य उपलब्ध जानकारी दी जा सकती है। प्राप्त सूचनाओं को आवश्यक समन्वय और सहायता के लिए मेघालय के संबंधित प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। असम सरकार और असम पुलिस मेघालय के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं और जरूरतमंद लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हेल्पलाइन नंबर : व्हाट्सऐप-9181014888, लैंडलाइन- 03612381511 आम लोगों से शांत रहने और प्रभावी एवं समयबद्ध समन्वय के लिए केवल सत्यापित जानकारी साझा करने की अपील की गई है। ज्ञात हो कि मेघालय की राजधानी एवं आसपास के इलाकों में बीते 19 अगस्त को खासी स्टूडेंट यूनियन (केएसयू) के द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान असम नंबर के वाहनों पर हमला कर उसमें तोड़-फोड़ की गयी। जिसके बाद बीते 20 अगस्त को असम-मेघालय सीमावर्ती खानापारा एवं जोराबाट में मेघालय के वाहनों का असम में प्रवेश करने से असम के वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों ने रोक दिया। इस घटना के बाद मेघालय की ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गयी है। इसका असर आज भी देखा जा रहा है। दोनों राज्यों में पुलिस प्रशासन हालात पर नजर रखते हुए हैं। सरकार की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है।

कामरूप में कृषि बुनियादी ढांचा कोष पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

रंगिया (विभास)। कामरूप जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के तत्वावधान में आज एकीकृत जिला आयुक्त कार्यालय के सभागार में कृषि बुनियादी ढांचा कोष के संबंध में एक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों, प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों सहित 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में के जिला आयुक्त देव कुमार मिश्रा, अतिरिक्त जिला आयुक्त (कृषि) देवाशीष गोस्वामी और कृषि बुनियादी ढांचा कोष के राज्य नोडल अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में भाषण देते हुए जिला आयुक्त ने कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के महत्व पर बल दिया। विशेष रूप से उन्होंने फसल कटाई के बाद के प्रबंधन, भंडारण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन

के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा, अन्य अतिथियों ने कृषि बुनियादी ढांचे से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे और योजना की पात्रता मानदंड, ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता, ब्याज छूट तथा ऋण गारंटी प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमियों और अन्य पात्र हितधारकों को कृषि बुनियादी ढांचा कोष के तहत उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और अवसरों से अवगत कराया गया। साथ ही, कृषि बुनियादी ढांचा कोष का लाभ उठाने की प्रक्रिया, पात्र परियोजनाओं के चयन, आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी और जमीनी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों को बैंकों की ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया और अन्य सरकारी योजनाओं के साथ कृषि बुनियादी ढांचा कोष के अभिसरण की संभावनाओं के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में उल्लेख किया गया कि कामरूप जिले में आधुनिक कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण, कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की सुविधाएं बनाने में कृषि बुनियादी ढांचा कोष की अपार संभावनाएं हैं। यह आशा व्यक्त की गई कि उन्नत बुनियादी ढांचा कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। इस अवसर पर सहायक कृषि निदेशक, के जिला कृषि अधिकारी, कामरूम के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, पलाशबाड़ी विधायक के प्रतिनिधि, स्टेट बैंक के उप प्रबंधक, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक, पीएमएफएमई, एफपीओ के प्रतिनिधि, उप-विभागीय कृषि अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, कृषि विस्तार सहायक, ब्लॉक प्रौद्योगिकी प्रबंधक और सहायक प्रौद्योगिकी प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी और संबंधित हितधारक उपस्थित रहे।

गोसाईगांव हाट रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग से 70 बोतल अवैध शराब बरामद

कोकराझाड़ (विभास)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अलीपुरद्वार मंडल अंतर्गत आरपीएफ पोस्ट कोकराझाड़ के अधीन आरपीएफ आउटपोस्ट गोसाईगांव हाट रेलवे स्टेशन की टीम ने *ऑपरेशन सतर्क* के तहत कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में लावारिस शराब बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार, आरपीएफ की एक विशेष टीम, जिसमें एसआईपीएफ एके मलाकार, एएसआई अमल राय और हेड कांस्टेबल डीके नार्जारी शामिल थे, स्टेशन परिसर में असामाजिक तत्वों, नशाखुरानी, मानव तस्करी व प्रतिबंधित सामानों की रोकथाम को लेकर सघन तलाशी अभियान चला रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गश्त के दौरान टीम की नजर लावारिस पड़े दो पिठू बैगों पर पड़ी। लगभग 30 मिनट तक निगरानी रखने और आसपास मौजूद यात्रियों से पूछताछ के बावजूद जब किसी ने बैग पर अपना दावा नहीं किया, तब गवाहों की मौजूदगी में बैग की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दोनों बैगों से *ऑफिसर्स चॉइस प्रीमियम व्हिस्की* की कुल 70 बोतलें बरामद हुईं। इनमें 375 मिलीलीटर की 20 बोतलें और 180 मिलीलीटर की 50 बोतलें शामिल हैं, जो केवल असम में बिक्री के लिए मान्य थीं। बरामद शराब का कुल अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 7,650 आंका गया है। आरपीएफ ने सभी शराब की बोतलों को जब्त कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग, गोसाईगांव को सौंप दिया। आबकारी विभाग ने इस संबंध में असम आबकारी अधिनियम 2000 की धारा 53(1)ए के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

असम सरकार की ओर से द्वि-वार्षिकी सतिया दिवस का आयोजन किया गया

विश्वनाथ (विभास)। असम सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय तत्वावधान नदुवार विधानसभा क्षेत्र के विधायक पद्म हजारिका के निर्तित्व व सभी जनता के सहयोग से दूसरी बार सतिया दिवस का आयोजन किया गया। इस गौरवमय माहौल में सुबह 10 बजे ऐतिहासिक थाना परिसर में तिरंगा झंडा फहराया कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शोणितपुर जिला पुलिस अधीक्षक वरुण पुरुकायस्थ ने की। इसके के बाद शहीद वेदी पर दीप प्रज्ज्वलन व पुष्पांजलि अर्पित किया गया। इस कार्यक्रम में गुवाहाटी विश्वविद्यालय की अवकाश प्राप्त अध्यापिका तथा मुक्तियोध्या डिंबेश्वर हजारिका की बेटी रानी काकोती ने भी भाग लिया। विधायक पद्म हजारिका ने स्वागत भाषण में सतिया दिवस पर विस्तार से प्रकाश डाला। सतिया नाट्य भवन में सभा

का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि असम सरकार सांस्कृतिक मंत्री बिमल बोरा के साथ वरिष्ठ अतिथि न्यूज चैनल डीवाई 365 के मुख्य संपादक अदीप कुमार फुकन उपस्थित थे। सभा का संचालन उदय शंकर सैकिया ने किया, संपादक अदीप कुमार फुकन ने अपने भाषण में कहा सतिया का भौगोलिक परिचय ही नहीं सतिया का स्वाधीनता संग्राम में एक गौरवमयी इतिहास भी जुड़ा हुआ है। सतिया में सन् 1942 के 20 अगस्त को महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की आग लगी थी, जो एक बहुत बड़े शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरा था। उसी समय सतिया पुलिस थाना परिसर में बिना खून खराबे के तिरंगा झंडा फहराया गया था जो आज पूरे देश में सतिया को एक अन्यतम मर्यादा प्रदान किया है असम सरकार सांस्कृतिक मंत्री बिमल बोरा ने भी शहीदों का स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि दी ओर कहा उन महान शहीदों के बलिदान को आज के नवप्रजन्म के बीच देश भक्ति की चेतना ओर इतिहास को याद रखने के लिए सतिया दिवस जैसे आयोजन का होना विशेष महत्व है मंत्री बिमल बोरा ने विधायक पद्म हजारिका प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी कर्मशील संस्कृति की यात्रा से भी युवाओं को सीखने के लिए बहुत कुछ है। विधायक पद्म हजारिका ने महान वीरों को याद करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व

विश्वनाथ के पावै से जोड़ने वाले बाईपास पर फ्लाइओवर की मांग जारी

विश्वनाथ चारियाली (विभास)। विश्वनाथ के *मृत्युदूत* बन चुके पावै जोड़ने वाले बाईपास पर एक फ्लाईओवर (उड़न सेतु) की मांग यहां के लोगों द्वारा लगातार की जा रही थी। इस स्थान पर बार-बार होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में पहले ही कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, विश्वनाथ के विभिन्न संगठनों और जनता ने इस जगह पर एक फ्लाईओवर के निर्माण की मांग उठाई थी। कुछ दिन पहले ही वहां एक और सड़क दुर्घटना होने के बाद, जनता ने एक बार फिर उपायुक्त (डीसी) को ज्ञापन सौंपा, जिसके परिणामस्वरूप प्रशासन इस बाईपास पर एक ट्रैफिक प्वाइंट बनाने के लिए मजबूर हुआ। विश्वनाथ के विधायक पल्लव लोचन दास ने इस प्वाइंट का शुभारंभ किया।

छठी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, रानीगुली का सीमावर्ती क्षेत्र में नि:शुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन

कोकराझाड़ (विभास)। छठी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), रानीगुली द्वारा जन-कल्याण योजना के अंतर्गत भारत-भूटान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्र के वेस्ट सरलपारा गांव में नि:शुल्क पशु चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह शिविर वाहिनी की बाह्य सीमा चौकी सरलपारा के कार्यक्षेत्र अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों के पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना तथा पशुधन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। शिविर का संचालन क्षेत्रक मुख्यालय, बोंगाईगांव के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. यतींद्र सिंह सेंगर, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में किया गया। शिविर में सीमा चौकी सरलपारा के अंतर्गत आने वाले गांवों

के पशुपालकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा अपने पशुधन की स्वास्थ्य जांच एवं उपचार कराया। कार्यक्रम के दौरान कुल 59 मवेशियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आवश्यकतानुसार उनका उपचार किया गया तथा नि:शुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। विशेषज्ञों द्वारा पशुपालकों को पशुओं के पोषण, नियमित टीकाकरण, स्वच्छता, रोगों की रोकथाम एवं वैज्ञानिक पशुपालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की गई। इस अवसर पर सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीणों एवं पशुपालकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ पशुधन संरक्षण के प्रति जागरूक करना तथा सीमा क्षेत्र में जन-सेवा, विश्वास एवं सहभागिता की भावना को और अधिक सुदृढ़ करना है। ग्रामीणों एवं पशुपालकों ने छठी वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल, रानीगुली द्वारा आयोजित इस नि:शुल्क पशु चिकित्सा शिविर की सराहना करते हुए बल के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं तथा ग्रामीण समुदाय और सशस्त्र सीमा बल के बीच आपसी विश्वास एवं सहयोग को और अधिक मजबूत करते हैं।

संपादकीय

ईरान बनेगा 'जापान'!

यह महज एक सवाल नहीं है अथवा आश्चर्य की मनःस्थिति नहीं है या चौंकाऊ खबर नहीं है कि अमरीका ईरान पर परमाणु हमला करेगा या नहीं! मानवीय और युद्धों के इतिहास में सिर्फ एक ही परमाणु हमला दर्ज है, जब अमरीका ने 6 और 9 अगस्त, 1945 को जापान के दो शहरों-हिरोशिमा और नागासाकी-पर एटम बम गिराए थे और शहरों को मिट्टी-मलबे में तबदील कर दिया था। क्रमशः करीब 1,40,000 और करीब 74,000 लोग मारे गए थे। महीनों और सालों बाद भी विकिरण के भयानक प्रभाव सामने आते रहे और बीमारियों से मरने वालों की संख्या अनगिनत है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के उस दौर में सिर्फ अमरीका ही परमाणु सम्पन्न देश था। सोवियत संघ ने 29 अगस्त, 1949 को सफल परमाणु परीक्षण किया और ब्रिटेन ने 1951 में परमाणु परीक्षण किया, लिहाजा अमरीका के लिए, कोई तात्कालिक विध्वंसकारी चुनौती नहीं थी। आज स्थितियां और समीकरण बिल्कुल भिन्न हैं। आज रूस के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार हैं। चीन के पास भी करीब 620 परमाणु हथियार बताए जाते हैं और वह रूस, अमरीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा शस्त्रागार है। हम रूस और चीन का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देश ईरान के 'अभिन्न मित्र' हैं और युद्ध के दौरान हथियारों, मिसाइलों, ड्रोन, वायु रक्षा प्रणालियां, सेटेलाइट रणनीतिक तस्वीरें आदि ईरान को मुहैया कराते रहे हैं। अमरीका इस यथार्थ को बखूबी जानता है। बीते दिनों राष्ट्रपति ट्रंप, उनके कुछ मंत्री, सामरिक सलाहकार, जनरल आदि 'कैंप डेविड' गए थे और गोपनीय बैठकें हुई थीं। राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक और करीबी रहे सांसदों के भी बयान सार्वजनिक हुए थे, लिहाजा परमाणु हमले की आशंकाएं उभरीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा है कि उन्हें युद्ध समाप्त करने की हड़बड़ी नहीं है। अभी तक अमरीका ने हल्की सैन्य ताकत का ही इस्तेमाल किया है। अब अमरीका-इजरायल मिल कर ईरान पर निर्णायक हमला करेंगे। इस बयान की व्याख्या की गई चूंकि पांच माह से भी लंबी जंग के बावजूद अमरीका ईरान को घुटनों पर नहीं ला सका है, लिहाजा अब 'निर्णायक हमला' परमाणु का ही किया जा सकता है। हालांकि इस संदर्भ में राष्ट्रपति ट्रंप का कोई बयान अथवा आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ है, फिर भी सवालिया आशंकाएं जताई जा रही हैं कि क्या अमरीका ईरान को 'जापान' बना सकता है? गौरतलब यह है कि अमरीकी राष्ट्रपति के बयान के बिना ही ईरान ने पलटजवाब दिया है कि यदि अमरीका ने परमाणु हमला किया, तो उसे उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। सवाल है कि क्या ईरान ने 'परमाणु बम' बना लिया है? हालांकि ईरान अब भी 'परमाणु अप्रसार संधि' (एनपीटी) का सदस्य है, लेकिन एक साल से अधिक समय से 'अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी' (आईएईए) ईरान के परमाणु कार्यक्रम का निरीक्षण नहीं कर पा रही है। उसे यह भी पुष्ट जानकारी नहीं है कि ईरान में कितना यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा है! अमरीका-इजरायल के कई हमलों के बावजूद ईरान के परमाणु केंद्र-नतांज, बुशहर, इस्फहान, फोर्दो आदि-यथावत और सुरक्षित बताए जाते हैं। सवाल है कि क्या अमरीका अब उन केंद्रों पर सीमित परमाणु हमले अथवा परमाणु सम्पन्न मिसाइल या बम से हमले कर उन्हें बिल्कुल नष्ट कर देना चाहता है? यह अमरीका का युद्ध थोपने का एक बुनियादी मकसद भी था। लेकिन उस स्थिति में विकिरण फैलेगा, तो कितनी मौतें होंगी? कितना विनाश होगा? खाड़ी देश का अधिकांश हिस्सा उस परमाणु विकिरण की चपेट में आ सकता है! शायद अमरीका इन यथार्थों को भी जानता है! लिहाजा रक्षा विशेषज्ञों के आकलन हैं कि अमरीकी परमाणु हमले की संभावनाएं नगण्य हैं! राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे बयानों के जरिए ईरान को सिर्फ डराना और उसे दबाव में लाने की रणनीति खेल रहे हैं। दोनों देशों के बीच शांति के जिस समझौता-दस्तावेज पर दस्तखत किए गए थे, उसकी अधिकारिक अवधि 17 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। दोनों देश अब हमले करने या युद्ध को विस्तार देने को स्वतंत्र हैं! यदि राष्ट्रपति ट्रंप ने अब ईरान के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इंकार कर दिया है, तो ईरान ने भी ऐसी किसी संभावना को खारिज कर दिया है।

अमरीका ने 6 और 9 अगस्त, 1945 को जापान के दो शहरों- हिरोशिमा और नागासाकी-पर एटम बम गिराए थे और शहरों को मिट्टी-मलबे में तबदील कर दिया था। क्रमशः करीब 1,40,000 और करीब 74,000 लोग मारे गए थे। महीनों और सालों बाद भी विकिरण के भयानक प्रभाव सामने आते रहे और बीमारियों से मरने वालों की संख्या अनगिनत है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के उस दौर में सिर्फ अमरीका ही परमाणु सम्पन्न देश था। सोवियत संघ ने 29 अगस्त, 1949 को सफल परमाणु परीक्षण किया और ब्रिटेन ने 1951 में परमाणु परीक्षण किया, लिहाजा अमरीका के लिए कोई तात्कालिक विध्वंसकारी चुनौती नहीं थी। आज स्थितियां और समीकरण बिल्कुल भिन्न हैं। आज रूस के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार हैं। चीन के पास भी करीब 620 परमाणु हथियार बताए जाते हैं और वह रूस, अमरीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा शस्त्रागार है। हम रूस और चीन का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशईरान के 'अभिन्न मित्र' हैं और युद्ध के दौरान हथियारों, मिसाइलों, ड्रोन, वायु रक्षा प्रणालियां, सेटेलाइट रणनीतिक तस्वीरें आदि ईरान को मुहैया कराते रहे हैं।

कुछ अलग

उम्र के अनुसार थाली

उम्र केवल कैलेंडर में बदलता हुआ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इसके साथ शरीर की जरूरतें भी बदलती हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई बदलाव धीरे-धीरे आते हैं और इन बदलावों के साथ खानपान में बदलाव आवश्यक हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की पाचन क्रिया और मेटाबॉलिज्म धीमी हो जाती है तथा मांसपेशियों और हड्डियों की स्थिति में भी बदलाव आने लगता है। इसके अलावा शरीर की ऊर्जा जरूरत भी कम होने लगती है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ भोजन की थाली में भी बदलाव जरूरी है। आमतौर पर आजकल 40 वर्ष की उम्र तक पहुंचते ही ये मान लिया जाता है कि अब बीमारियां लगने का समय आ गया है, लेकिन ये एक गलत धारणा है। असलियत में यह एक ऐसा पड़ाव है जिसमें यदि व्यक्ति अपने खानपान और जीवनशैली को लेकर थोड़ा अधिक सजग हो जाए, तो आने वाले वर्षों के स्वास्थ्य की मजबूत नींव रख सकता है। भोजन में जरूरी पोषक तत्वों को शामिल करना, नमक-चीनी और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को सीमित करना तथा नियमित शारीरिक गतिविधि को जीवन का हिस्सा बनाना इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई बदलाव धीरे-धीरे आते हैं। चयापचय की गति में बदलाव, मांसपेशियों को बनाए रखने की चुनौती, हड्डियों के स्वास्थ्य की चिंता और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का बढ़ता जोखिम खानपान को लेकर अधिक सजग रहने का संकेत देता है। खासकर 40 वर्ष की उम्र के बाद यह समझना जरूरी हो जाता है कि जो भोजन 20 या 30 की उम्र में आसानी से पच जाता था और शरीर की जरूरतें पूरी करता था, वही भोजन बढ़ती उम्र में उसी मात्रा और तरीके से लेना हमेशा उचित नहीं हो सकता।

धर्म और आलोचनात्मक चिंतन को एक-दूसरे का विरोधी मानना एक बड़ी भूल है

आस्था का सम्मान, लेकिन गलत बातों पर सवाल जरूरी

धर्म मनुष्य के जीवन में केवल पूजा-पद्धति या कर्मकांड का विषय नहीं है। वह उसकी आस्था, संस्कृति, नैतिकता, परंपरा और जीवन-दृष्टि से जुड़ा हुआ विषय है। धार्मिक ग्रंथों ने हजारों वर्षों से समाज को नैतिक मूल्यों, कर्तव्य, करुणा, संयम, सत्य और परोपकार का संदेश दिया है। यही कारण है कि करोड़ों लोग धार्मिक पुस्तकों को श्रद्धा के साथ पढ़ते और अपने जीवन में उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन श्रद्धा का अर्थ यह नहीं हो सकता कि किसी भी पुस्तक में लिखी प्रत्येक बात को बिना प्रश्न किए, बिना संदर्भ समझे और बिना तर्क की कसौटी पर परखे स्वीकार कर लिया जाए। आज सबसे जरूरी प्रश्न यही है कि क्या धार्मिक पुस्तकों में लिखी हर बात को अक्षरशः सत्य मानना चाहिए? यदि किसी कथन में ऐतिहासिक परिस्थिति की छाप है, यदि वह किसी विशेष सामाजिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है, यदि उसका अर्थ आज के संदर्भ में अलग हो गया है या यदि किसी कथन की व्याख्या मनुष्य के बीच भेदभाव को बढ़ावा देती है, तो उस पर सवाल उठाना क्या धर्म-विरोध है? निश्चित रूप से नहीं। सवाल करना ज्ञान की पहली सीढ़ी है और स्वस्थ समाज की पहचान भी। धर्म और आलोचनात्मक चिंतन को एक-दूसरे का विरोधी मानना एक बड़ी भूल है। आस्था व्यक्ति का निजी विश्वास हो सकती है, लेकिन जब किसी धार्मिक विचार की व्याख्या सार्वजनिक जीवन, कानून, शिक्षा, सामाजिक संबंधों या नागरिक अधिकारों को प्रभावित करने लगे, तब उस विचार पर सार्वजनिक विमर्श स्वाभाविक और आवश्यक हो जाता है। लोकतंत्र में किसी विचार को केवल इसलिए आलोचना से मुक्त नहीं किया जा सकता कि वह धार्मिक संदर्भ से आया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा—धर्म की आलोचना और धार्मिक व्यक्ति का अपमान अलग-अलग बातें हैं। किसी धार्मिक पुस्तक के किसी कथन, उसकी व्याख्या या उसके सामाजिक प्रभाव पर प्रश्न उठाना किसी धर्मावलंबी के सम्मान को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। आलोचना विचार की होनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं। तर्क का जवाब तर्क से दिया जाना चाहिए, भावनात्मक आक्रोश से नहीं। हमारे समाज में अक्सर यह प्रवृत्ति दिखाई देती है कि जब किसी धार्मिक ग्रंथ की किसी बात पर प्रश्न उठता है तो चर्चा का केंद्र उस प्रश्न का उत्तर देने के बजाय प्रश्न पूछने वाले की नीयत बन जाती है। उसे धर्म-विरोधी, परंपरा-विरोधी या समाज-विरोधी कह दिया जाता है। इससे संवाद बंद होता है और कट्टरता बढ़ती है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर उपलब्ध है तो उसे शांतिपूर्वक सामने रखा जाना चाहिए। यदि किसी कथन की अलग-अलग व्याख्याएँ हैं तो उन पर चर्चा होनी चाहिए। और यदि कोई बात ऐतिहासिक संदर्भ में थी, तो उसके संदर्भ को समझाया जाना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों को उनके समय और परिस्थितियों से काटकर पढ़ना भी समस्या पैदा कर सकता है। हजारों वर्ष पहले का समाज आज के समाज जैसा नहीं था। उस समय की सामाजिक संरचना, शासन

धार्मिक ग्रंथों ने हजारों वर्षों से समाज को नैतिक मूल्यों, कर्तव्य, करुणा, संयम, सत्य और परोपकार का संदेश दिया है। यही कारण है कि करोड़ों लोग धार्मिक पुस्तकों को श्रद्धा के साथ पढ़ते और अपने जीवन में उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन श्रद्धा का अर्थ यह नहीं हो सकता कि किसी भी पुस्तक में लिखी प्रत्येक बात को बिना प्रश्न किए, बिना संदर्भ समझे और बिना तर्क की कसौटी पर परखे स्वीकार कर लिया जाए। आज सबसे जरूरी प्रश्न यही है कि क्या धार्मिक पुस्तकों में लिखी हर बात को अक्षरशः सत्य मानना चाहिए? यदि किसी कथन में ऐतिहासिक परिस्थिति की छाप है, यदि वह किसी विशेष सामाजिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है, यदि उसका अर्थ आज के संदर्भ में अलग हो गया है या यदि किसी कथन की व्याख्या मनुष्य के बीच भेदभाव को बढ़ावा देती है, तो उस पर सवाल उठाना क्या धर्म–विरोध है? निश्चित रूप से नहीं। सवाल करना ज्ञान की पहली सीढ़ी है और स्वस्थ समाज की पहचान भी।

व्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान, परिवार व्यवस्था और आर्थिक परिस्थितियाँ अलग थीं। इसलिए किसी प्राचीन कथन का अर्थ समझने के लिए उसके मूल संदर्भ, भाषा, प्रतीकों और तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। आधुनिक समय में उसी कथन की शाब्दिक व्याख्या करने से कई बार ऐसी धारणाएँ पैदा हो सकती हैं जो मूल संदर्भ से बिल्कुल अलग हों। इसीलिए धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन केवल श्रद्धा से नहीं, बल्कि ज्ञान, इतिहास, भाषा और दर्शन की दृष्टि से भी होना चाहिए। श्रद्धा मनुष्य को प्रेरणा देती है, जबकि विवेक उसे सही अर्थ समझने में सहायता करता है। दोनों का संतुलन समाज को अधिक परिपक्व बनाता है। सबसे संवेदनशील विषय तब सामने आता है जब किसी धार्मिक कथन की व्याख्या के आधार पर स्त्री-पुरुष असमानता, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, हिंसा, सामाजिक बहिष्कार या किसी वर्ग के प्रति घृणा को उचित ठहराने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय पर है। इसलिए कोई भी व्याख्या यदि मनुष्य की गरिमा को कम करती है तो उस पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। यहाँ संविधान की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अलग-अलग धर्म, संप्रदाय, भाषाएँ और परंपराएँ साथ-साथ रहती हैं। हमारा सामाजिक जीवन किसी एक धार्मिक ग्रंथ के आधार पर नहीं, बल्कि संविधान द्वारा निर्धारित नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के आधार पर संचालित होता है। प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक आस्था का अधिकार है, लेकिन साथ ही दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का सम्मान करना भी आवश्यक है। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता और आलोचनात्मक चिंतन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। किसी को अपनी आस्था रखने से रोका नहीं जाना चाहिए और किसी को अपनी आस्था के नाम पर दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती। एक और चुनौती है—धार्मिक ग्रंथों की मनमानी व्याख्या। कई बार मूल पुस्तक से अधिक प्रभाव उसकी व्याख्या करने वालों का होता है। एक ही कथन की अलग-अलग विद्वान अलग व्याख्या करते हैं। कोई उसे प्रतीकात्मक मानता है, कोई ऐतिहासिक, कोई आध्यात्मिक और कोई शाब्दिक। ऐसे में यह कहना कि केवल एक व्याख्या ही अंतिम सत्य है, बौद्धिक रूप से उचित नहीं कहा जा सकता। समाज में धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य भी केवल यह नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति क्या माने, बल्कि यह भी होना चाहिए कि वह क्यों माने। यदि बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो उनकी आस्था समाप्त नहीं होगी; बल्कि संभव है कि उनकी समझ अधिक गहरी हो जाए। जिस विश्वास को प्रश्नों से डर लगता है, वह विश्वास कमजोर हो सकता है; लेकिन जो विश्वास प्रश्नों का सामना कर सकता है, वह अधिक परिपक्व और मजबूत बनता है। आज डिजिटल युग में यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो गया है। सोशल मीडिया पर धार्मिक पुस्तकों के नाम पर आधे-अधूरे उद्धरण, गलत अनुवाद और संदर्भ से काटे गए कथन तेजी से फैलते हैं। लोग कई बार मूल ग्रंथ देखे बिना ही किसी वायरल पोस्ट को सत्य मान लेते हैं। इससे धार्मिक विवाद पैदा होते हैं और सामाजिक तनाव बढ़ता है। इसलिए किसी कथन पर आपत्ति करने से पहले यह देखना आवश्यक है कि वह वास्तव में मूल ग्रंथ में है भी या नहीं, उसका सही अनुवाद क्या है और उसके आगे-पीछे का संदर्भ क्या है। आलोचना करने वाले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है। यदि वह किसी धार्मिक पुस्तक के किसी कथन पर सवाल उठा रहा है तो उसे प्रमाण, संदर्भ और तर्क के साथ बात रखनी चाहिए। जानबूझकर गलत उद्धरण देना, किसी धर्म के अनुयायियों को अपमानित करना या धार्मिक भावनाओं को भड़काना आलोचनात्मक चिंतन नहीं है। वह केवल विवाद पैदा करना है। इसी प्रकार धार्मिक विद्वानों की भी जिम्मेदारी है कि वे आलोचना को शत्रुता न समझें। समाज बदलता है, भाषा बदलती है और प्रश्न भी बदलते हैं। यदि कोई पुरानी व्याख्या आज के संदर्भ में समस्या पैदा करती है तो उस पर पुनर्विचार करना धर्म की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी जीवंतता का संकेत हो सकता है। धार्मिक परंपराओं में स्वयं आत्ममंथन की लंबी परंपरा रही है। संतों, दार्शनिकों और सुधारकों ने समय-समय पर रूढ़ियों पर प्रश्न उठाए। उन्होंने समाज को यह समझाने का प्रयास किया कि धर्म का मूल उद्देश्य मनुष्य को जोड़ना, नैतिक बनाना और उसके भीतर करुणा पैदा करना है, न कि मनुष्य को मनुष्य से अलग करना। इस संदर्भ में हमें एक व्यापक सिद्धांत अपनाना चाहिए—जो बात मानवता, करुणा, सत्य, न्याय और समानता को मजबूत करती है, उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए; और जो बात इन मूल्यों के विपरीत दिखाई दे, उस पर प्रश्न उठाने से डरना भी नहीं चाहिए। यह दृष्टिकोण किसी एक धर्म तक सीमित नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी एक धार्मिक परंपरा की पुस्तकों में लिखी बातों पर सवाल उठाने को स्वतंत्रता मानते हैं, तो यही स्वतंत्रता दूसरी धार्मिक परंपराओं के मामले में भी लागू होनी चाहिए।

देश दुनीया से

लोकतंत्र में शैक्षणिक आजादी की अहमियत

जब मैंने हालिया वी-डेम एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स (शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक) को देखा, तो मुझे झटका तो लगा, लेकिन कोई ज्यादा हैरानी भी नहीं हुई। झटका इसलिए लगा कि शैक्षणिक स्वतंत्रता के मामले में 179 देशों में भारत का स्थान निचले 10-20 प्रतिशत देशों में है। मेरा दुख और बेचैनी इसलिए और बढ़ गई कि 1990 के बाद से भारत की स्थिति अब तक की सबसे खराब है, यहां तक कि 1975-1977 के आपातकाल के दौर से भी नीचे है। तथापि, दो कारणों से मुझे हैरानी नहीं होती। पहला, मुझे लगता है कि हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्वतंत्रता की भावना की उम्मीद करना बहुत भोलापन होगा, खासकर ऐसे समय में जब राजनीतिक-सांस्कृतिक व्यवस्था, अपनी कथित दकियानूसी और संभावित रूप से तानाशाही वाली प्रकृति के कारण, स्वतंत्र सोच के प्रकाश से असहज बनी हुई हो। दरअसल, ताकत का विरोधाभास यही है : आप जितने अधिक शक्तिशाली होते हैं, उतने ही अधिक डरपोक भी होते जाते हैं। यह असहमति का डर है; यह एक वैकल्पिक नजरिए का डर है; और यह आलोचनात्मक सोच का डर है जो शक्तिशाली सत्ताधारी शासन, या उसके 'सर्वोच्च' नेता की सावधानीपूर्वक बनाई गई भव्य छवि को बिगाड़ सकती है। यह भय संक्रामक है। जहां एक ओर यह उस होनहार प्रोफेसर से डरता है जो अपनी पढ़ाई और लेखन के जरिए पितृसत्तात्मक समाज, महिलाओं के प्रति नफ़रत और अति-पुरुषवादी धार्मिक राष्ट्रवाद पर सवाल उठाता है, वहीं दूसरी ओर यह 19 साल के कॉलेज छात्र को भी नहीं बख्शता, मसलन, जो राजसत्ता द्वारा फैलाई धारणा

से परे हटकर उमर खालिद की प्रतिभा को समझना चाहता है, या स्टेन स्वामी और प्रो. जी.एन. साईबाबा जैसे लोगों के संघर्षों और उपलब्धियों के बारे में जानना चाहता है। वहीं इस डर की तीव्रता की कल्पना कीजिए- जिस तरह हमारे राजनीतिक तौर पर नियुक्त कुछ कुलपति सत्ताधारी शासन को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और इस तरह विश्वविद्यालय के उस मूल विचार को ही कमज़ोर कर देते हैं जो कई ज्ञान-परंपराओं के मिलन का केंद्र होता है। तो क्या हैरानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में,एक अन्य प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति ने कुछ जाने-माने समाज-वैज्ञानिकों का उपहास करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की, क्योंकि उन्होंने बताए जा रहे 'तथ्यों' के क्रम को उलट-पलट दिया था? शायद, भारतीय ज्ञान प्रणाली की श्रेष्ठता में उनके अटूट विश्वास ने ही उन्हें आधुनिक नारीवादियों के समूह को 'सुधारने' के लिए प्रेरित किया '! संदेश साफ़ है। 'भारतीय ज्ञान प्रणाली' के नाम पर होने वाली हर चीज़ का महिमामंडन करें, और आलोचनात्मक सोच की भावना को कार्ल मार्क्स, ज्यां-पॉल सार्त्र और मिशेल फूको जैसे लोगों से उधार लिया गया महज़ एक 'पश्चिमी' विचार बताकर कमतर आंकें! दूसरी बात, यह अहसास होना भी उतना ही ज़रूरी है कि वे चतुर शिक्षाविद् जो अक्सर 'मूल्य-तटस्थता' के नाम पर अपनी ज़िम्मेदारियों से बचते हैं और चुप रहना पसंद करते हैं, वे भी कम ज़िम्मेदार नहीं हैं। वे भी अकादमिक स्वतंत्रता की भावना को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें कब समझ आएगा कि 'तटस्थता' की यह बात महज़ एक भ्रम है? भ्रामक प्रचार मशीनरी के इस दौर में, हम अज्ञानता को हथियार बनते देख रहे हैं। हम जबरदस्ती वाले राष्ट्रवाद का बदसूरत रूप देख रहे हैं; सार्वजनिक जीवन में शालीनता और बातचीत की संस्कृति का लगातार पतन होता हम अनुभव कर रहे हैं। ऐसे हालात में कोई 'तटस्थ' कैसे रह सकता है? असल में, यह तथाकथित 'तटस्थता' अनिवार्य रूप से यथास्थिति को मंजूरी देने जैसी है। अगर आप 'तटस्थ' और चुप रहते हैं, जबकि आपके साथी अपने किसी लेक्चर और लेखन की वजह से परेशान, अपमानित और निलंबित किए जाते हैं, तो आप न सिर्फ़ एक शिक्षाविद् के तौर पर नाकाम हो जाते हैं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर भी विफल हो रहे होते हैं; और आख़िरकार, आप उन्हीं ताक़तों को मज़बूत करते हैं जिन्हें स्वतंत्र जांच-पड़ताल की भावना से नफ़रत है। यह अच्छा होगा अगर भौतिकी और रसायन शास्त्र के प्रोफ़ेसर भी अपनी 'मूल्य-तटस्थ' और सुरक्षित लैब से बाहर निकलें और यह समझें कि अकादमिक स्वतंत्रता के बिना विज्ञान भी तरक्की नहीं कर सकता। इसे स्वीकार करना होगा। अकादमिक आज़ादी खत्म होने से पूरे देश के सांस्कृतिक ताने-बाने को भारी नुकसान होगा। अगर हम बहस करने, संवाद और आज़ाद सोच-विचार की संस्कृति खोते रहे, तो हमारा लोकतंत्र एक तरह से सिर्फ़ चुनावों के जरिए चलने वाली तानाशाही बनकर रह सकता है। लोकतंत्र का भविष्य लोगों की सोचने और संसद में भेजे गए नेताओं से सवाल पूछने की क्षमता पर निर्भर करता है। और यह तभी हो सकता है जब हमारे स्कूल और विश्वविद्यालय ऐसे नागरिक तैयार करें जो बौद्धिक रूप से जागरूक हों और संवाद में यकीन रखते हों। असल में, अब यह समझने का समय आ गया है कि विचार शक्ति विहीन व्यक्ति और एक जागरूक नागरिक के बीच बड़ा फ़र्क होता है। वह जो आत्म-मुग्धता या सत्ता के अहंकार पर सवाल उठाने वाला और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से विनम्रता, जवाबदेही और दूसरों की बात को सहानुभूति से सुनने की मांग करे। अगर हमारे शिक्षण संस्थान सिर्फ़ मशीनी, डरे हुए या आज्ञाकारी नागरिक तैयार करेंगे, तो लोकतंत्र फल-फूल नहीं पाएगा। चहुं ओर फैली गिरावट के बीच निराशावाद के जाल में फंसना आसान है।

आप का नजरीया

अस्पताल में खौफ

कोई भी अस्पताल बीमार व अशक्त लोगों के जीवन की अंतिम किरण होती है। एक विश्वास का प्रतीक कि वहां से स्वस्थ होकर लौटेंगे। तरह-तरह के रोगों से पीड़ितों का अस्पताल पर भरोसा होता है कि वहां पहुंचकर उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन यदि किसी अस्पताल में उपचार के लिये गई महिला के साथ जांच के नाम पर दुराचार हो और वीभत्स कृत्य उसे मौत के मुंह में धकेल दे तो इससे ज्यादा व भयावह कुछ नहीं हो सकता। यह घटना लाखों मजबूर-बीमार लोगों तथा महिलाओं के भरोसे को तोड़ती है, जब यह पता चलता है कि वीभत्स घटना एक सरकारी अस्पताल में हुई है। हरियाणा के पानीपत स्थित अस्पताल के सीटी स्कैन रूम में एक 58 साल की महिला के साथ हुए दुराचार और उसके बाद रोहतक के पीजीआईएमएस में उपचार के दौरान उसकी मौत ने लाखों लोगों के भरोसे को भी तोड़ा है। निस्संदेह, कानून अपना काम करेगा, पुलिस की जांच अपराधी को सख्त दंड दिलाने में मददगार होगी, लेकिन इस घटना ने संस्थागत सुरक्षा इंतजामों की चिंताजनक नाकामी को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। सबसे अधिक विचलित करने वाली बात यह है कि आरोपी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तरह अस्पताल की सीटी स्कैन और एमआरआई यूनिट चलाने वाली एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। लेकिन सवाल यह उठता है कि वह कथित तौर पर सीटी स्कैन टेक्नीशियन का काम कैसे कर रहा था? निस्संदेह, सरकारी अस्पताल के अंदर इस तरह से दायित्वों की भूमिका में बदलाव होना व्यवस्था की ऐसी नाकामियों की तरफ इशारा करता है, जो किसी व्यक्ति के कुकृत्य से कहीं अधिक आगे की बात है। निस्संदेह, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना अस्पताल व अन्य सार्वजनिक संस्थानों में देख-रेख, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के पालन और जवाबदेही को लेकर विचलित करने वाले सवाल खड़े करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा के बुनियादी नियम-कानून एक साथ निरर्थक हो गए हैं। सवाल यह है कि पहले ही रोगों, शारीरिक जीर्णता, मानसिक तनावों से गुजर रहे लोगों की सुरक्षा हेतु क्या कोई कायदे-कानून नहीं हैं? उनकी सुरक्षा महज राम भरोसे है? सरकारी अस्पतालों में मरीजों को कितने धक्के खाने पड़ते हैं और पक्की नौकरी वालों का आमतौर पर मरीजों से व्यवहार कैसा होता है, वह सर्वविदित है। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें मरीज के साथ स्कैन-रूम में नहीं जाने दिया गया। वहां कोई महिला स्टॉफ मौजूद नहीं थी। दुर्भाग्य से महिला मरीज को ऐसे व्यक्ति के भरोसे छोड़ दिया गया, जिसे वास्तव में वहां खड़े रहने का भी हक नहीं था। ये चिकित्सा प्रक्रिया की कोई मामूली चूक नहीं है। ऐसी खामी में शोषण का खतरा लगातार बना रहेगा। विगत में भी कई ऐसी घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान खींचा, जहां महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई। वर्ष 1973 में मुंबई के केईएम अस्पताल में नर्स अरुणा शानबाग के साथ जानलेवा यौन-हिंसा हुई थी। इसी तरह की कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कालेज की दुखद घटना, जिसमें यौन हिंसा से मेडिकल की छात्रा की मौत हुई थी। विडंबना यह कि घटना का जमकर राजनीतिक दोहन तो होता है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होते ही सुधार के वायदे भी हवा हो जाते हैं। एक बार फिर पानीपत की दुखद घटना ने बताया है कि हमारे नीति-नियंताओं की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। निश्चित रूप से पानीपत में हुई वीभत्स घटना को महज एक अपराध की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इस घटना के मद्देनजर मरीजों की सुरक्षा से जुड़े नीतिगत फैसलों में बदलाव लाया जाना चाहिए। ऐसे अस्पताल व सार्वजनिक सेवा केंद्रों से जुड़े, प्रत्येक आउटसोर्स किए गए विकल्पों की समीक्षा की जानी चाहिए। तैनात कर्मचारियों की कारगुजारियों-भूमिकाओं का सत्यापन किया जाना चाहिए। अस्पतालों में सीसीटीवी कवरेज का दायरा विस्तृत व मजबूत किया जाना चाहिए।

अस्पताल में उपचार के लिये गई महिला के साथ जांच के नाम पर दुराचार हो और वीभत्स कृत्य उसे मौत के मुंह में धकेल दे तो इससे ज्यादा व भयावह कुछ नहीं हो सकता। यह घटना लाखों मजबूर–बीमार लोगों तथा महिलाओं के भरोसे को तोड़ती है, जब यह पता चलता है कि वीभत्स घटना एक सरकारी अस्पताल में हुई है। हरियाणा के पानीपत स्थित अस्पताल के सीटी स्कैन रूम में एक 58 साल की महिला के साथ हुए दुराचार और उसके बाद रोहतक के पीजीआईएमएस में उपचार के दौरान उसकी मौत ने लाखों लोगों के भरोसे को भी तोड़ा है। निस्संदेह, कानून अपना काम करेगा, पुलिस की जांच अपराधी को सख्त दंड दिलाने में मददगार होगी, लेकिन इस घटना ने संस्थागत सुरक्षा इंतजामों की चिंताजनक नाकामी को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। सबसे अधिक विचलित करने वाली बात यह है कि आरोपी पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप के तरह अस्पताल की सीटी स्कैन और एमआरआई यूनिट चलाने वाली एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। लेकिन सवाल यह उठता है कि वह कथित तौर पर सीटी स्कैन टेक्नीशियन का काम कैसे कर रहा था? निस्संदेह, सरकारी अस्पताल के अंदर इस तरह से दायित्वों की भूमिका में बदलाव होना व्यवस्था की ऐसी नाकामियों की तरफ इशारा करता है, जो किसी व्यक्ति के कुकृत्य से कहीं अधिक आगे की बात है।

दृष्टि कोण

दिमागी नक्सल को लेकर नई बहस

पिछले दिनों पंद्रह अगस्त के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में से नक्सल आतंक को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन कुछ दिमागी नक्सल अभी भी बचे हुए हैं। इसको लेकर बहुत हो हल्ला हुआ। कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। लेकिन गुस्से में आने वालों को एक ही तराजू पर नहीं तोला जा सकता। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो सचमुच ही दिमागी नक्सलवादी हैं। वे अभी तक चुपचाप अपना काम कर रहे थे। उनके इस 'चुपचाप काम' का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा था, लेकिन इन छिपे दिमागी नक्सलवादियों की किसी को भनक तक नहीं लग रही थी। जैसे कोई शातिर चोर अचानक चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो वह समय की नजाकत को भांप कर राबिनहुड बनने की कोशिश करता है। इस प्रथम कैटेगरी में पी. चिदंबरम आते हैं। दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की है जिसको न नक्सलवाद से कुछ लेना-देना है और न ही उनका इससे कुछ लेना-देना है। क्योंकि मोदी ने कहा है कि कुछ छिपे हुए दिमागी नक्सल अभी भी बचे हुए हैं, इससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि क्योंकि मोदी अपने विरोधी दल वालों को तरह तरह से उकसाते हैं, इसलिए जरूर ये दिमागी नक्सल इंडी गठबंधन में होंगे। अब इंडी गठबंधन में उनको वह स्थान नहीं मिल रहा जो पहले मिला करता था। ऐसे लोगों को लगा कि इंडी गठबंधन में अपनी खोई हैसियत दोबारा पाने का यह सुनहरी मौका है। उनको लगा देश की जनता यह मान लेगी कि मोदी से जो विरोधी नेता लड़ सकता है, वह वही है जो इस वक्त ज्यादा चिल्लाएगा कि वह दिमागी नक्सल है। इस कैटेगरी में दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल आते हैं। अभी नरेंद्र मोदी का लाल किला का संबोधन शायद पूरा भी नहीं हुआ था कि केजरीवाल ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि वह ही सबसे बड़ा दिमागी नक्सलवादी है। केजरीवाल को लगा कि राहुल गांधी जब भी भारत में आते हैं, तो चीख चिल्ला कर बताना शुरू कर देते हैं कि विरोधी पक्ष का मैं ही नेता हूं। मोदी मुझसे डरते हैं। इस प्रकार लड़ाई मोदी बनाम राहुल बनती है। यह देखकर

केजरीवाल ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि वह सबसे बड़े दिमागी नक्सलवादी हैं। वैसे भी केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत ही इस मंत्र से की थी। वे वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। दिमागी नक्सल के लिए भी दिमाग चाहिए। यह सूत्र बहुत से लोग अपने आप को दिमागी नक्सल कहने की हड़बड़ी में भूल ही गए। एक तीसरी श्रेणी भी मंच पर उतरी। उसने भी दावा किया है कि वह दिमागी नक्सल है। उस कैटेगरी में कश्मीर घाटी की महबूबा मुफ्ती हैं। अचानक न जाने उसको क्या सूझी कि अरविंद केजरीवाल को चिल्लाते देख कर महबूबा मुफ्ती ने भी मुंडेर पर आकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे पहचानो, मैं भी दिमागी नक्सल ही हूं। लेकिन महबूबा मुफ्ती भूल गईं कि इस्लाम में नक्सलवादी पैदा नहीं होते, बल्कि वहां वे नकाब में नमूदार होते हैं। इसलिए महबूबा मुफ्ती के मामले पर जाने से पहले यह जान लेना जरूरी हो गया है कि आखिर दिमागी नक्सलवादी का अर्थ क्या है? अपने वक्त में एक यहूदी कार्ल माक्र्स ने बहस चलाई थी कि संसार को बदलने के लिए, उसमें आम लोगों को शामिल करने और उनकी राय को समझने बूझने की जरूरत नहीं है। संसार को बदलने का, सिस्टम को बदलने का निर्णय चंद गिने चुने लोग ही करते हैं। यह जरूरी तो नहीं 'संसार बदल देने' के उनके इस निर्णय से लोग सहमत ही हों। इसका उत्तर मिल चुका था कि उनकी राय की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि लोग उनके इस प्रयोग का विरोध ही शुरू कर दें। इसका उत्तर था कि परिवर्तन बंदूक से आता है।

भारत-जापान की युवा पीढ़ी का मिलन, मुख्यमंत्री आवास पर गूंजा दोस्ती और भविष्य का संदेश

लखनऊ, (हि.स.)। मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसमें कूटनीति की औपचारिकता की जगह बच्चों की मुस्कान थी, भाषाओं की दूरी की जगह संवाद था और दो देशों की संस्कृति के बीच दोस्ती का सहज सेतु बनता दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश-जापान निवेश बैठक के क्रम में आयोजित विशेष कार्यक्रम ए डायलॉग विद द फ्यूचर में जापान के यामानाशी प्रान्त से आए 13 विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी प्रान्त के गवर्नर कोटारो नागासाकी की मौजूदगी में हुआ यह संवाद आने वाले भारत-जापान संबंधों की उस तस्वीर को सामने ला रहा था, जिसकी नींव आज की युवा पीढ़ी के मन में रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने जापान के यामानाशी से आए विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों तथा लखनऊ के युवा साथियों का आत्मीय स्वागत करते हुए जापानी अभिवादन 'ओहायो गोजाइमासु' से अपने संबोधन की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ से अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख केंद्र है और इसे हार्टलैंड ऑफ इंडिया के रूप में भी देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस अवध क्षेत्र में आज यह संवाद हो रहा है, उसी क्षेत्र में अयोध्या स्थित है। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि है। जापानी विद्यार्थियों ने आगरा में ताजमहल देखा, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि देखा। अब वाराणसी तथा सारनाथ जाने का अवसर उन्हें मिलेगा। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। वाराणसी दुनिया की प्राचीनतम नगरियों में से एक है। इस तरह जापान से आए इन विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश की यात्रा भारत की आध्यात्मिकता, संस्कृति और सभ्यतागत विरासत को करीब से जानने का अवसर भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल विद्यार्थियों का मिलन नहीं है। यह दो संस्कृतियों, दो परंपराओं और दो देशों की युवा पीढ़ियों का मिलन है। अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे समय में दोनों देशों के ये विद्यार्थी भविष्य के राजदूत के रूप में इस संबंध को नई ऊंचाई देने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर भारत की सबसे बड़ी युवा कार्यशक्ति वाले उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं और दूसरी ओर तकनीक, परंपरा और प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाने वाले जापान के बच्चे। एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी लेकिन दोनों के बीच सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान से आए विद्यार्थियों के लिए भारत की विविधता में एकता, वसुधैव कुटुम्बकम्, भारतीय भाषाओं, दर्शन, पर्व और त्योहारों तथा उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक

विरासत को समझने का यह अवसर है। उन्होंने कहा कि जापान की नई पीढ़ी भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं बल्कि एक साझा सभ्यतागत मित्र के रूप में जाने, यह इस संवाद की बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं, भारतीय विद्यार्थियों के लिए जापान की कार्य संस्कृति, जीवन दर्शन, अनुशासन, इकीगाई, टीमवर्क, पारस्परिक सम्मान, स्वच्छता, समयबद्धता, पारंपरिक कलाओं और उत्सवों को समझने का अवसर है। उन्होंने कहा कि आदान-प्रदान कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि दोनों देश एक-दूसरे से सीखें और अपनी श्रेष्ठ बातों को साझा करें। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने जापान के सामाजिक सामंजस्य के दर्शन और भारत के वसुधैव कुटुम्बकम की वैचारिकी के बीच की सुंदर समानता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति मानती है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। 'अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।' उन्होंने कहा कि यह अपना है और यह पराया है, ऐसी सोच संकुचित मन वाले लोगों की होती है, उदार चरित्र वाले लोगों के लिए पूरी दुनिया ही एक परिवार है। इसी भावना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के संकल्प में भी देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान की स्ट्रेंथ सेल्फ डिसिप्लिन, प्रिसिजन, क्वालिटी, टीम वर्क और इनोवेशन में है, जबकि भारत की शक्ति युवा शक्ति, प्रतिभा, विविधता, सृजनात्मकता और सबको साथ लेकर चलने की भावना में है। जब जापान की शक्ति और भारत की शक्ति साथ आएंगी, तो इसका लाभ केवल दोनों देशों के बच्चों को नहीं मिलेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर नई संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आज वे विद्यार्थी हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में इन्हीं में से वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, कलाकार, खेल चैंपियन, नीतिनिर्माता और वैश्विक नेतृत्वकर्ता निकलेंगे। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि वे एक-दूसरे की भाषा सीखने के साथ एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का भी प्रयास करें। एक-दूसरे की संस्कृति, मूल्यों और जीवन दृष्टि का सम्मान करें। यामानाशी प्रान्त के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने दोनों देशों के विद्यार्थियों को संवाद का यह अवसर दिया। उन्होंने लखनऊ के विद्यार्थियों का भी विशेष धन्यवाद किया, जिन्होंने जापानी बच्चों का आत्मीय स्वागत किया। गवर्नर ने कहा कि दोनों देशों को और बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे बीच क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं। उन्होंने भारत के वसुधैव कुटुम्बकम और यामानाशी की उस सोच का उल्लेख किया, जिसमें एक-दूसरे के लोगों को समृद्ध बनाने के साथ अपनी समृद्धि को भी सुनिश्चित करने की भावना है। गवर्नर कोटारो नागासाकी ने कहा कि यह मुलाकात केवल एक दिन का कार्यक्रम बनकर नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने जापानी और भारतीय मित्रों के साथ इस दोस्ती को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश साथ मिलकर समृद्ध हों और युवा पीढ़ी इस रिश्ते को और मजबूत बनाए, यही इस संवाद की सबसे बड़ी अपेक्षा है। मुख्यमंत्री और जापानी गवर्नर के संबोधन के बाद संवाद और भी आत्मीय हो गया। जापानी विद्यार्थियों ने मिलकर जापानी भाषा में गीत प्रस्तुत किया। उनकी सामूहिक प्रस्तुति के दौरान मुख्यमंत्री आवास का वातावरण तालियों से गूंज उठा। इसके जवाब में भारत की ओर से ईशान ने भगवान श्रीराम को समर्पित 'कौशल्या दशरथ के नंदन' गीत प्रस्तुत किया। लखनऊ की छात्रा अक्षरा पांडेय ने जापानी विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी यहां आए, यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि जापानी विद्यार्थियों को ताजमहल पसंद आया, यह उनके लिए भी सुखद है। जापानी विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव खुलकर साझा किए। जापानी छात्र कजामा ने कहा, भारत आना मेरे लिए बहुत खास अनुभव है क्योंकि मैं पहली बार अपने देश से बाहर निकला हूं। यहां आकर जिस तरह लोगों ने हमसे मित्रवत व्यवहार किया, वह मेरे दिल को छू गया। भारत की सड़कों पर इतनी सारी मोटरसाइकिल और गाड़ियां देखना मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। टोक्यो में ऐसा अनुभव कम मिलता है। मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को हुआ यह कार्यक्रम अंततः निवेश और आर्थिक साझेदारी से कहीं आगे निकलकर मानवीय रिश्तों का उत्सव बन गया। यहां 13 जापानी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों से मिले, अपनी भाषा में गीत सुनाया, ओरिगेमी के माध्यम से शांति और मित्रता का संदेश दिया और भारत के अनुभव अपने साथ लेकर लौटने की तैयारी की। वहीं, भारतीय विद्यार्थियों ने जापानी संस्कृति को करीब से जाना और अपनी संस्कृति की झलक उन्हें दिखाई। एक तरफ यामानाशी के बच्चे थे, दूसरी तरफ लखनऊ के बच्चे। भाषाएं अलग थीं, संस्कृतियां अलग थीं, लेकिन भविष्य का सपना एक था। यही ए डायलॉग विद द फ्यूचर की सबसे बड़ी तस्वीर रही, आज की दोस्ती से कल की मजबूत भारत-जापान साझेदारी की नींव।

मायावती ने कहा- सरकारें फायदे के लिए बदलती रहती हैं कानून

लखनऊ, (हि.स.)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने वंदे मातरम् गायन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। जनता का ध्यान बांटने के लिए नई सरकारें अपने फायदे के लिए पुरानी सरकारों के कानूनों को बदलती रहती हैं। मायावती ने शुक्रवार को कहा कि देश में वंदेमातरम् गायन को पूरा गाना है या शुरू के दो छंद (पैरा) गाना है। या नहीं गाना है, इसको लेकर जो इस समय में देश में राजनीति चल रही है, यह ठीक नहीं है। इस मामले में हमारी पार्टी का यही कहना है कि वंदेमातरम गायन को लेकर अभी हाल ही में संसद में जो कानून पास

किया गया है यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्यों में भी सत्ता परिवर्तन के दौरान सभी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ के हिसाब से या फिर अपनी कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए यह सब करती रहती हैं। एक-दूसरे के बने कानूनों को बदलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि इस समय बेरोजगार युवाओं, जेन-जी, जी-अल्फा और बाढ़ जैसे अनेक मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। देश व जनहित में समय की सबसे जरूरी मांग यही है।

नृपेंद्र मिश्र ने कहा, मैंने चंपत राय की चिट्ठी नहीं देखी

अयोध्या,(हि.स.)। श्रीराम जन्मभूमि के निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन शुक्रवार को श्रीराम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर नृपेंद्र मिश्रा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों को प्रगति की जानकारी दी और कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनना करोड़ों श्रद्धालुओं के सपने का साकार होना है। उन्होंने श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की गुरुवार को जारी चिट्ठी में अपना नाम होने के सवाल पर कहा कि उन्होंने पत्र देखा ही नहीं है और आप लोग विवाद कराना चाहते हैं। मंदिर निर्माण में केंद्र या राज्य सरकार का पैसा नहीं लगा, ट्रस्ट द्वारा एकत्रित धन से निर्माण कराया गया। उन्होंने बताया कि तय किए गए करीब 70 निर्माण कार्यों में से लगभग 60 कार्य पूरे हो चुके हैं। पूरे हो चुके निर्माण कार्यों को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा गया, अब रखरखाव ट्रस्ट

करेगा। परिसर में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या दूर करने के लिए सीवेज और ड्रेनेज व्यवस्था को मुख्य नाले से जोड़ने का काम किया जाएगा। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि संग्रहालय, ऑडिटोरियम और ट्रस्ट कार्यालय के निर्माण पर अब विशेष ध्यान है।। संग्रहालय की गैलरी नंबर-7 पर करीब 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यहां प्रवेश शुल्क लगेगा या नहीं, इसका फैसला ट्रस्ट करेगा। राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ की नियुक्ति के साक्षात्कार के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

कल्याण सिंह के आदर्श एवं विचार सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे : केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ,(हि.स.)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित सरकारी आवास, सात कालिदास मार्ग पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, 'पद्म विभूषण' से सम्मानित कल्याण सिंह 'बाबूजी' की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि श्रद्धेय कल्याण सिंह का संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा, जनकल्याण और सांस्कृतिक स्वाभिमान के प्रति अटूट समर्पण की प्रेरणादायी मिसाल है। उनके आदर्श एवं विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बात जब राष्ट्रवाद के विरोध और तुष्टीकरण के जरिए वोट साधने

की हो तो कांग्रेस व समाजवादी पार्टी (सपा) दोनों एक ही कुंड में गोता लगाने में कतई परहेज नहीं करते हैं। देश के स्वाभिमान से समझौता करने में दोनों एक-दूसरे पर बीस हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रगीत वंदे मातरम से परहेज है। वहीं समाजवादी पार्टी राग अलाप रही है कि उसकी सरकार बनने पर अपने उस तुर्रम खां मुस्लिम नेता को गृह मंत्री बनाएगी जो भारत माता को डायन कहता रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की बात करने पर दोनों कान में तेल डालकर सो जाते हैं। दोनों दलों को समझना चाहिए 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने तक जनता न तो उत्तर प्रदेश में सपा को सत्ता सौंपने वाली है और न देश की बागडोर कांग्रेस को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार देश और प्रदेश को दिन दूनी, रात चौगुनी गति से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रही हैं। मोदी का ईमानदार नेतृत्व विकास, सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित है। जनता को देश बनाने वाले चाहिए, लूटने वाले नहीं। विकास करने वाले चाहिए, दंगा और तुष्टीकरण कराने वाले नहीं। कांग्रेस 'सांपनाथ' है और सपा 'नागनाथ'। इनसे जनता को बचाना भाजपा का राष्ट्रधर्म है।

गाय की बलि का आरोप, ग्रामीणों ने की ग्राम प्रधान को हटाने की मांग

पूर्वी सिंहभूम, (हि.स.)। पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांदा प्रखंड की बालिजुड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत बेनागाड़िया राजस्व ग्राम में जाहेर स्थान पर गाय की बलि दिए जाने के आरोप को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर अंचल अधिकारी गुड़ाबांदा, उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, घाटशिला के देश परगना तथा बालिजुड़ी पंचायत की मुखिया को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान गैर-पारंपरिक अथवा चुनावी ग्राम प्रधान बालिराम हेम्ब्रम द्वारा अपने सहयोगियों सिंगराई हेम्ब्रम और कारान टुडू के सहयोग से गांव के पवित्र जाहेर स्थान में गाय की बलि दी गई, जिससे गांव के विभिन्न समूहों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आवेदन में ग्रामीणों ने बताया है कि जाहेर स्थान संथाल समुदाय का पवित्र धार्मिक स्थल है और वहां इस तरह की गतिविधि को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व पारंपरिक ग्राम प्रधान शशि हेम्ब्रम ने गाय-भैंस की बलि का

विरोध किया था। इसके बाद उन्हें ग्राम प्रधान के पद से हटाकर बालिराम हेम्ब्रम को गैर-पारंपरिक चुनावी ग्राम प्रधान बनाया गया।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जाहेर स्थान में मौजूद धार्मिक महत्व के पेड़ को बेचने को लेकर भी विवाद उत्पन्न हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से वर्तमान ग्राम प्रधान बालिराम हेम्ब्रम को पद से हटाने तथा उनका मानदेय बंद करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पेसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान शशि हेम्ब्रम को पुनः ग्राम प्रधान नियुक्त करने की मांग प्रशासन के समक्ष रखी है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि जब तक विवाद का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक गांव में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से उचित व्यवस्था की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद के कारण गांव में सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए प्रशासन मामले की जांच कर ग्रामीणों की शिकायतों पर गंभीरता से विचार करे और परंपरागत व्यवस्था तथा ग्राम समुदाय की सहमति के अनुरूप उचित निर्णय ले। आवेदन सौंपने के दौरान बालिराम हेम्ब्रम, शुकुंतला मुर्मू, फुलमंत्री टुडू, बाघराय मुरमु, चातुर मुर्मू, शन्नो मुर्मू, श्रीमती मुर्मू, चेंदुआ माकन मुन्ना, लिलमनी मुर्मू, बंसा मुर्मू, सोनामनी मुर्मू, दलपते मुर्मू, अहानी मनी मुर्मू, सीता राम हेम्ब्रम सहित कई ग्रामीणों मौजूद रहे।

पुल निर्माण में लगे दो मजदूरों को अपराधियों ने मारी गोली

पलामू,(हि.स.)। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के रजडेरवा में गुरुवार देर रात नेशनल हाईवे (एनएच) पर पुल निर्माण स्थल पर काम कर रहे दो मजदूरों को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमएमसीएच) लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया। घटना रात करीब 11 बजे की है। घायल मजदूरों के मुताबिक, बाइक पर सवार कुछ अपराधी काम कर रहे मजदूरों के पास पहुंचे और उनसे माचिस मांगी। मजदूरों ने माचिस नहीं होने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और बाइक सवार अपराधियों ने दोनों मजदूरों पर गोली चला दी। गोली लगने से दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े। उनकी पहचान 26 वर्षीय अजय हांसदा और 20 वर्षीय संजय हांसदा के रूप में हुई है। दोनों पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाले हैं। घटना के बाद अपराधी बाइक से मौके से फरार हो गए। वहां मौजूद अन्य मजदूरों ने तत्काल दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को घटना की सूचना दी। रात एक बजे एमएमसीएच में इलाज के लिए घायलों को लाया गया। वहीं, वारदात के बाद एनएच पर काम कर रहे मजदूरों में भय का माहौल है।

पूर्वी सिंहभूम में चौकीदार के 58 पद खाली, नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू कराने की मांग

पूर्वी सिंहभूम,(हि.स.)। पूर्वी सिंहभूम जिले में चौकीदार के 58 रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को कुछ लोगों ने उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने का आग्रह किया। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले में बड़ी संख्या में चौकीदार के पद खाली रहने से संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि रिक्त पदों के कारण विभागीय स्तर पर कार्यों के संचालन में परेशानी आ रही है। वहीं, दूसरी ओर इन पदों पर नियुक्ति नहीं होने से योग्य और इच्छुक युवाओं को रोजगार का अवसर भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में रिक्त पदों को जल्द भरने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर पहल करने की जरूरत है। ज्ञापन सौंपने वालों ने उपायुक्त से मांग

की कि चौकीदार के सभी 58 रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि बहाली पूरी होने से न केवल विभाग में मानव संसाधन की कमी दूर होगी, बल्कि संबंधित क्षेत्रों में चौकीदारों से जुड़े कार्यों का भी बेहतर तरीके से संचालन हो सकेगा। साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। आवेदनकर्ताओं ने जिला प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने का आग्रह किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द आवश्यक कार्रवाई करेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में अजय महतो, रबी मिस्मा, योगेंद्र टांडे और प्रसनजीत महतो शामिल थे।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में शिक्षा ऋण कम होने की खबर को विभाग ने बताया तथ्य से परे

पटना, (हि.स.)। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को मिलने वाले शिक्षा ऋण में कमी किए जाने की खबर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के दायरे को और बढ़ाया है। सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार अब 2 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं 2 लाख से 4 लाख तक की वित्तीय सहायता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ही 4 लाख तक की राशि उपलब्ध कराई जाती थी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल और बैंकों से जोड़ने का उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए संस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसके

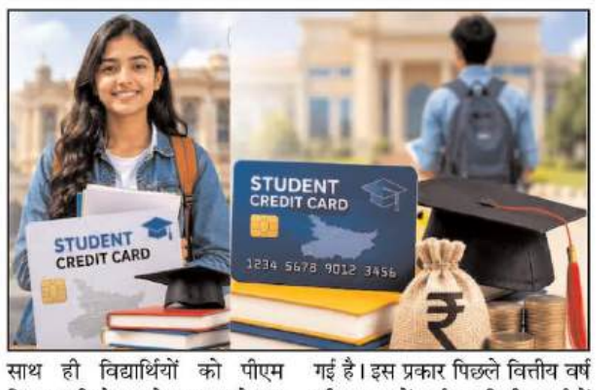

साथ ही विद्यार्थियों को पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को पहले की तुलना में वित्तीय सहायता के अब अधिक विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 886 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी गई थी। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 950 करोड़ के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के लिए 64 करोड़ अधिक व्यय की स्वीकृति दी गई है। आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वित्तीय सहायता का प्रावधान घटा नहीं, बल्कि बढ़ा है। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आसान, व्यापक और संस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंचाना है।

एमएसकेबी स्कूल में लगातार दूसरी रात चोरी, पेयजल संकट से आक्रोशित छात्रों ने किया सड़क जाम

मुजफ्फरपुर, (हि.स.)। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित महिला शिल्प कला भवन (एमएसकेबी) विद्यालय में लगातार दूसरी रात चोरी की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। चोरों ने स्कूल के कमरों के ताले तोड़कर पंखे और अन्य सामान चोरी करने के साथ सबमर्सिबल मोटर का पाइप भी उखाड़ लिया। इससे स्कूल परिसर में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया। आक्रोशित छात्रों और स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को बनारस बैंक चौक के समीप सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। करीब डेढ़ घंटे तक यातायात बाधित रहा। जानकारी के अनुसार, बुधवार रात चोरों ने स्कूल के दो कमरों के ताले तोड़कर पंखे और अन्य सामान चोरी कर लिए थे। प्रधानाध्यापक ने इसकी लिखित शिकायत नगर थाने में की थी। इसके बावजूद गुरुवार देर रात चोरों ने दोबारा स्कूल परिसर में प्रवेश किया। इस बार तीन कमरों के ताले तोड़कर पंखे चोरी कर लिए गए। चोर सबमर्सिबल मोटर का पाइप उखाड़कर ले गए और उसके ऊपर बने शेड को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। शुक्रवार सुबह शिक्षक और छात्राएं स्कूल पहुंचे तो परिसर में पानी की व्यवस्था ठप मिली। भीषण गर्मी में पेयजल संकट से आक्रोशित छात्र-छात्राएं स्थानीय लोगों के साथ सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने बनारस बैंक चौक के पास मुख्य मार्ग जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्कूल के प्राचार्य प्रभात रंजन ने नगर थाना पुलिस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्कूल की बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा पिछले छह महीने से टूटा हुआ है। उनके अनुसार, यह स्थान अपराधियों, जुआरियों और नशेड़ियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। दिन ढलने के बाद असामाजिक तत्व वहां जुटते हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस को कई बार लिखित और मौखिक रूप से इसकी जानकारी दी गई, लेकिन गश्त बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि पहली चोरी के बाद पुलिस सख्त कार्रवाई करती तो लगातार दूसरी रात चोरी की घटना नहीं होती। सड़क जाम की

सूचना मिलने पर नगर थानेदार जय प्रकाश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों और स्कूल कर्मियों को समझाकर शांत कराया और यातायात बहाल कराया। थानेदार ने चोरी की घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और चोरी में शामिल लोगों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।

सर्राफा बाजार में महंगा हुआ सोना, चांदी ने भी लगाई बड़ी छलांग

नई दिल्ली

अमेरिकी बान्ड मार्केट में आई गिरावट का असर दुनिया भर के बुलियन मार्केट में नजर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों चमकीली धातुओं ने जोरदार छलांग लगाई है। सोना और चांदी के भाव में आई वैश्विक तेजी का असर घरेलू सर्राफा बाजार में भी शुरुआती कारोबार के दौरान नजर आ रहा है। देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना 3,970 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 4,320 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। इसी तरह चांदी के भाव में 10,200 रुपये प्रति किलोग्राम तक की उछाल दर्ज की गई है।

कीमत में हुए इस बदलाव के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,59,280 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,59,430 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,46,010 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,46,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी तेजी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,55,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,59,430 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,160 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,59,280 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,46,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,59,330 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,060 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,59,280 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,46,010 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,59,280 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,46,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,330 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,46,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,59,430 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,46,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,330 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,46,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,59,430 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,46,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोना शुरुआती कारोबार के दौरान जबरदस्त मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,59,280 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

न्यूज ब्रीफ

टाटा मोटर्स वाहनों की कीमतों में 25 हजार तक का करेगी इजाफा, नई कीमतें एक सितंबर से लागू

नई दिल्ली। मारुति, हुंडई के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (टीएमपीवी) ने अपने वाहनों की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान किया है। वाहन विनिर्माता टीएमपीवी अपने सभी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के दाम में 25 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी करेगी। नई कीमतें एक सितंबर 2026 से लागू होंगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि टीएमपीवी एक सितंबर से अपने सभी वाहनों की कीमतों में 25 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने इसकी वजह बढ़ती लागत और महंगाई के दबाव को बताया है। यह सभी खंडों के आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) और ईवी की कीमतों में बढ़ोतरी माडल एवं संस्करण के आधार पर अलग-अलग होगी। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने कहा, बढ़ती लागत और महंगाई के प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित करने के लिए कीमतों में यह बदलाव किया जा रहा है। यह बढ़ोतरी विभिन्न माडलों और वैरिएंट्स के आधार पर अलग-अलग होगी। टीएमपीवी अब भी इस बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही है, लेकिन संशोधन के जरिये इसका कुछ बोझ ग्राहकों पर डाला जा रहा है। उल्लेखनीय है कि टीएमपीवी के वाहन खंड में छोटी कार टियागो से लेकर प्रीमियम एसयूवी सफारी तथा हैरियर ईवी मुख्य रूप से शामिल है। इन वाहनों की कीमत लगभग 4.7 लाख रुपये से 31 लाख रुपये के बीच है।

पीएनबी की चेतावनी, निष्क्रिय खाते बंद होने का खतरा, तुरंत करें केवायसी अपडेट

मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपने लाखों ग्राहकों के लिए एक अहम चेतावनी जारी की है। बैंक ने ऐसे निष्क्रिय खातों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है जिनमें लंबे समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है और जिनका बैलेंस शून्य है। ग्राहकों को सितंबर तक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है, ताकि उनके खाते बंद होने से बच सकें। पीएनबी के अनुसार, ऐसे बैंक खाते जिनमें पिछले तीन साल से कोई लेनदेन दर्ज नहीं हुआ है और खाते में कोई राशि भी नहीं है, उन्हें बंद किया जा सकता है। बैंक ने यह कदम खातों के गलत इस्तेमाल और उनसे जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए उठाया है। पीएनबी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया माध्यमों पर भी यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसमें खाताधारकों को सचेत किया गया है। निष्क्रिय खाताधारक अपने खाते को बंद होने से बचाने के लिए सितंबर तक संबंधित बैंक शाखा में अपने केवायसी दस्तावेज जमा कराकर इसे दोबारा सक्रिय करवा सकते हैं। केवायसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्राहक बैंक की सेवाओं का इस्तेमाल जारी रख सकेंगे। बैंक ने यह भी सलाह दी है कि कोई भी ग्राहक अपना खाता बंद करने का निर्णय लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि यह पेंशन, सब्सिडी, लोन, बीमा या किसी अन्य महत्वपूर्ण भुगतान से जुड़ा न हो।

सेबी की बड़ी कार्रवाई, दो कंपनियों पर लगा प्रतिबंध, गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे जब्त करने का निर्देश

मुंबई। बाजार नियामक सेबी ने सेंसेक्स डेरिवेटिव्स अनुबंधों की साप्ताहिक अंतिम तिथि पर हुई कीमतों की असामान्य हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। एक विस्तृत जांच के बाद, सेबी ने जेपी मार्गन की मारीशस स्थित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) कापटाल मारीशस इन्वेस्टमेंट और मानसी शेयर एंड स्टाक ब्रोकिंग को बाजार में कीमतों की कृत्रिम छेड़छाड़ का दोषी पाया है। नियामक ने इन कंपनियों को शेयर बाजार में कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया है और उनसे गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे को जब्त करने का आदेश दिया है। यह मामला 13 अगस्त को क्लोजिंग आक्शन सेशन (सीएएस) के दौरान सेंसेक्स में कुछ ही सेकंड में हुई कीमतों की अचानक उछाल से जुड़ा है।

सब्सक्रिप्शन के लिए लान्च हुआ आगमान्ट इंटरप्राइजेज का आईपीओ, 31 अगस्त को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली

देश की प्रमुख इंटेग्रेटेड गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटफार्म मैनेजमेंट कंपनी आगमान्ट इंटरप्राइजेज लिमिटेड का 825 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लान्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 25 अगस्त तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 27 अगस्त को शेयरों का अलाटमेंट किया जाएगा, जबकि 28 अगस्त को अलाटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 31 अगस्त को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। लान्चिंग के बाद दोपहर एक बजे तक ये आईपीओ 1.22 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 750 रुपये से लेकर 788 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 19 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम एक लाट यानी 19 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 14,972 रुपये का निवेश करना होगा।

इसी तरह रिटेल इनवेस्टर 1,94,636 रुपये के निवेश से अधिकतम 13 लाट में 247 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ के तहत पांच रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 1,04,69,541 करोड़ शेयर जारी किए जा रहे हैं। इनमें लगभग 620 करोड़ रुपये के 78,68,020 नए शेयर जारी किए जा रहे हैं, जबकि लगभग 205 करोड़ रुपये के 26,01,521 शेयर आफर फार सेल विंडो के जरिये बेचे जा रहे हैं।

इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 49.76 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 34.83 प्रतिशत हिस्सा रखा गया है। इसके अलावा नान इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 14.93 प्रतिशत हिस्सा और एंप्लायीज के लिए 0.48 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इस इश्यू के लिए नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि एमयूजीएफ इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है।

आगमान्ट इंटरप्राइजेज लिमिटेड की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत बनी रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 75.97 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 227.19 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का शुद्ध लाभ उछल कर 348.30 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 34,948.90 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 66,252.05 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 94,282.47 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस अवधि में कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ भी लगातार घटता गया। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी पर 54.86 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में घट कर 21.54 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो इस वित्त वर्ष के दौरान कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ कम होकर 12.67 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

कंपनी का रिजर्व और सरप्लस भी इस अवधि में लगातार बढ़ता गया। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस 180.39 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो वित्त वर्ष वित्त वर्ष 2024-25 में उछल कर 398.46 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो इस दौरान कंपनी का रिजर्व और सरप्लस 865.14 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया था। इस अवधि में कंपनी के नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 204.87 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 422.94 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का नेटवर्थ 926.27 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

इसी तरह ईबीआईटीडीए (अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट, टैक्सेज, डिप्रेशिएशंस एंड एमार्टाइजेशन) 2023-24 में 103.92 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 304.09 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का ईबीआईटीडीए 385.95 करोड़ रुपये के स्तर पर था।

बंगाल का औद्योगिक सपना, दशकों का सफर और अनसुलझी तस्वीर

नई दिल्ली

कोलकाता की चमकीली शहरी छवि, औद्योगिक मोर्चे पर स्थायी बदलाव की चुनौती

पश्चिम बंगाल ने पिछले तीन दशकों में अपनी औद्योगिक और आर्थिक छवि को बदलने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। 1994 में वाम मोर्चा सरकार द्वारा निजी निवेश के द्वार खोलने से लेकर तृणमूल कांग्रेस के आईटी हब के प्रयासों तक, राज्य ने निवेश आकर्षित करने और अपनी उग्र मजदूर संघों वाली छवि से उबरने के लिए लगातार प्रयास किए हैं।

हालांकि, चमकदार शहरी विकास के बावजूद, राज्य की औद्योगिक तस्वीर अभी भी कई चुनौतियों से घिरी हुई है। सितंबर 1994 में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने मुख्यमंत्री ज्योति बसु के नेतृत्व में, निजी निवेश के लिए द्वार खोलते हुए एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। लाइसेंस राज के ढहने के बाद, राज्य ने चुनिंदा क्षेत्रों में नई तकनीक और निवेश का स्वागत किया।

हालांकि, अप्रैल 2000 में हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की शुरुआत हुई, लेकिन अनेक समझौता ज्ञापन (एमओयू) ठोस निवेश या रोजगार में तब्दील नहीं हो पाए। तब तक राज्य की पहचान उग्र मजदूर संघों और औद्योगिक अशांति वाले प्रदेश के रूप में स्थापित हो चुकी थी, जिससे निवेशक दूर भाग रहे थे। नवंबर 2000 में बुद्धदेव भट्टाचार्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ।

उनके अभी करो वाले दृष्टिकोण ने औद्योगीकरण को गति दी। कोलकाता में साल्ट लेक और राजारहाट जैसे क्षेत्रों में आईटी कंपनियों के परिसर, भव्य शापिंग माल और रेस्तरां तेजी से विकसित हुए। इन आधुनिक केंद्रों ने शहर के पुराने औपनिवेशिक स्वरूप से हटकर एक नई व्यावसायिक पहचान गढ़ी, जो कांच और इस्पात के टावरों से चमक उठी।

एचडीएफसी बैंक ने विदेशी बान्ड से जुटाए 1.75 अरब डालर

नई दिल्ली। देश एवं निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक ने कारोबार को बढ़ाने के लिए विदेशी बान्ड जारी कर 1.75 अरब अमेरिकी डालर जुटाए हैं। एचडीएफसी बैंक ने शेयर बाजार को रेगुलेटरी फाइलिंग में दी जानकारी में बताया कि गिफ्ट सिटी शाखा के जरिये 1.75 अरब अमेरिकी डालर के सीनियर अनसिक्योर्ड बान्ड जारी किए हैं। बैंक ने बताया कि उसने तीन साल में परिपक्व होने वाले 50 करोड़ अमेरिकी डालर के बान्ड 5.159 फीसदी की कूपन दर पर जारी किए हैं। वहीं, शेष 1.25 अरब यूएस डालर के पांच साल में परिपक्व होने वाले बान्ड पर कूपन दर 5.4 फीसदी है। एचडीएफसी बैंक ने बताया कि इन बान्ड को इंडिया आईएनएक्स (इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (आईएफएससी) लिमिटेड) और एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (एनएसई-आईएक्स) में सूचीबद्ध किया जाएगा। विदेशी बान्ड कर्ज जुटाने का साधन हैं, जिन्हें कोई कंपनी किसी दूसरे देश के बाजार से धन जुटाने के लिए जारी करती है। इन्हें संबंधित देश की स्थानीय मुद्रा या किसी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में जारी किया जा सकता है। भारतीय निवेशक उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत वैश्विक बाजारों में निवेश कर सकते हैं।

भारतीय प्राइवेट क्रेडिट बाजार गुलजार, रियल एस्टेट सबसे आगे

अगले 1-2 वर्षों में बाजार की मजबूती बरकरार रहने का अनुमान

नई दिल्ली

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्राइवेट क्रेडिट बाजार अगले एक से दो वर्षों में भी मजबूत बना रह सकता है। एच1 2026 में रियल एस्टेट सेक्टर ने इसमें अहम भूमिका निभाई, जबकि घरेलू निवेशकों ने वैश्विक फंड्स को पीछे छोड़ दिया। इस अवधि में करीब 3.5 अरब डालर का निवेश हुआ।

एक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2026 की पहली छमाही (एच1 2026) में भारत के प्राइवेट क्रेडिट बाजार में उल्लेखनीय विस्तार हुआ, जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत घरेलू आर्थिक आधार और बेहतर बैंकिंग सेक्टर से प्रेरित था। इस दौरान कुल निवेश लगभग 3.5 अरब डालर रहा, जिसमें घरेलू फंड्स का दबदबा रहा। कुल डील वैल्यू में घरेलू खिलाड़ियों की हिस्सेदारी 74 फीसदी रही, जबकि डील की संख्या में यह आंकड़ा 79 फीसदी रहा। सेक्टरवार विश्लेषण में रियल एस्टेट कुल प्राइवेट क्रेडिट डील वैल्यू के 35 फीसदी हिस्से के साथ सबसे आगे रहा, जिसके बाद हेल्थकेयर (13 फीसदी) का स्थान रहा।

एक महत्वपूर्ण बदलाव फूड एंड बेवरेज (एफएंडबी) सेक्टर में देखा गया, जिसकी हिस्सेदारी एच 2 2025 में मात्र 1 फीसदी से

बढ़कर एच1 2026 में 12 फीसदी पर पहुंच गई। यह तेजी भारतीय बैंकिंग सेक्टर की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति से भी प्रेरित है।

मार्च 2026 तक बैंकों का कैपिटल टू रिस्क-वेटेड एसेट्स रेश्यो 17.7 फीसदी और सीईटी1 अनुपात 15.3 फीसदी रहा। वित्तीय वर्ष 2026 में सकल एनपीए अनुपात घटकर 1.8 फीसदी और शुद्ध एनपीए 0.4 फीसदी रह गया, जो एसेट क्वालिटी में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है। सर्वे में शामिल 60 फीसदी प्रतिभागियों ने अगले 1-2 वर्षों के लिए भारतीय प्राइवेट क्रेडिट बाजार को लेकर सकारात्मक रुख जताया है। हालांकि, बढ़ती प्रतिस्पर्धा एक चिंता का विषय बनी हुई है। रियल एस्टेट, हालांकि सबसे सक्रिय सेक्टर है, इसे डिफाल्ट के लिहाज से सबसे जोखिम भरा भी माना गया है। स्ट्रेस, कैपेक्स और विलय-अधिग्रहण फाइनेंसिंग इस बाजार की प्रमुख मांग बने हुए हैं।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशिया में भी मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि डाउ जान्स फ्यूचर्स मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार दबाव बना रहा। वहीं एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है।

अमेरिका में 10 साल की बान्ड यील्ड के 4.7 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाने का असर वाल स्ट्रीट के कारोबार पर साफ-साफ नजर आया। डाउ जान्स 700 अंक से अधिक फिसल गया। इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 66.82 अंक यानी 0.87 प्रतिशत की गिरावट के साथ 7,641.16 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 263.92 अंक यानी एक प्रतिशत की कमजोरी के साथ 26,067.17 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डाउ जान्स फ्यूचर्स

फिलहाल 0.08 प्रतिशत की मजबूती के साथ 52,799.45 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान दबाव में कारोबार करने के बाद मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.04 प्रतिशत की मामूली तेजी के साथ 10,748.16 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसके विपरीत सीएसी इंडेक्स ने 0.58 प्रतिशत टूट कर 8,453.09 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 108.29 अंक यानी 0.42 प्रतिशत लुढ़क कर 25,983.04 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। एशिया के नौ बाजार में से छह के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में और तीन सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 0.14 प्रतिशत फिसल कर 24,263 अंक के स्तर पर आ गया है। इसी तरह निक्केई इंडेक्स 237.79 अंक यानी 0.36 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 65,979 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा शंघाई कंपोजिट इंडेक्स एक अंक की सांकेतिक कमजोरी के साथ 3,902.72 अंक के स्तर पर बना हुआ है।

दूसरी ओर, हैंग सेंग इंडेक्स 207.51 अंक यानी 0.81 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,906 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह कोस्पी इंडेक्स 51.37 अंक यानी 0.75 प्रतिशत की मजबूती के साथ 6,903.95 अंक के स्तर पर आ गया है। सेट कंपोजिट इंडेक्स फिलहाल 0.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,621.29 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.52 प्रतिशत उछल कर 6,535.30 अंक के स्तर पर, ताइवान वेटेड इंडेक्स 148.33 अंक यानी 0.33 प्रतिशत की छलांग लगा कर 45,082.07 अंक के स्तर पर और स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.13 प्रतिशत की उछाल के साथ 5,679.48 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

टेनिस प्रीमियर लीग का आठवां सत्र 8 से 13 दिसंबर तक, हैदराबाद करेगा मेजबानी

हैदराबाद

टेनिस प्रीमियर लीग (टीपीएल) का आठवां सत्र 8 से 13 दिसंबर 2026 तक हैदराबाद के एलबी टेनिस स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आठ फ्रेंचाइजी टीमों के बीच होने वाली इस लीग में रोमांचक 25 अंकों के प्रारूप में मुकाबले खेले जाएंगे।

अखिल भारतीय टेनिस संघ के तत्वावधान और तेलंगाना सरकार के सहयोग से होने वाले टीपीएल के आठवें सत्र में देश-विदेश के शीर्ष खिलाड़ियों के साथ भारत के प्रमुख टेनिस सितारे भी हिस्सा लेंगे। लीग के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण जियोहाटस्टार पर किया जाएगा।

आठ फ्रेंचाइजी टीमों के बीच मुकाबला

छह दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में जीएस दिल्ली एसेस, हैदराबाद स्ट्राइकर्स, लखनऊ ब्लेजर्स, गुरुग्राम ग्रैंड स्लैमर्स, गुजरात पैंथर्स, राजस्थान रेंजर्स, कोलकाता थंडर ब्लेड्स और मुंबई रायल्स खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी।

टीपीएल के 25 अंकों के प्रारूप में प्रत्येक अंक महत्वपूर्ण होता है। हैदराबाद में आयोजन के साथ लीग नए शहर और नए दर्शकों तक पहुंच बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाएगी।

लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा भी रहेंगी मौजूद

टीपीएल के आठवें सत्र में टेनिस दिग्गज लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा की मौजूदगी भी रहेगी। बालीवुड कलाकार और टीम की सह-मालिक रकुल प्रीत सिंह और सोनाली बेंद्रे बहल भी अपनी-अपनी टीमों का समर्थन करती नजर आएंगी।

लीग के मुताबिक, टीपीएल ऐप देशभर की 400 से अधिक संबद्ध टेनिस अकादमियों को जोड़ रहा है। अहमदाबाद में सातवें सत्र की सफलता के बाद अब हैदराबाद में आयोजन से लीग के राष्ट्रीय विस्तार को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

किआ इंडिया बनी विशेष साझेदार

आठवें सत्र में किआ इंडिया विशेष साझेदार के रूप में टीपीएल से जुड़ी है। टीपीएल के सह-संस्थापक कुणाल ठाकुर ने कहा कि हैदराबाद में विश्वस्तरीय टेनिस को पहली बार ले जाना और किआ इंडिया के साथ साझेदारी इस सत्र को लीग के लिए महत्वपूर्ण अध्याय बनाता है।

सह-संस्थापक मृणाल जैन ने कहा कि हर सत्र में टीपीएल नए शहरों और नए दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है और हैदराबाद इस यात्रा में अगला बड़ा कदम है। किआ इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (बिक्री एवं विपणन) अतुल सूद ने कहा कि हैदराबाद का खेलप्रेमी दर्शक वर्ग लीग को नया मंच देगा और कंपनी भारत में टेनिस के प्रति अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता को और मजबूत करना चाहती है।

तेलंगाना के नगर प्रशासन एवं शहरी विकास और खेल विभाग के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन ने कहा कि हैदराबाद प्रमुख खेल लीगों की मेजबानी के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि टीपीएल का आयोजन तेलंगाना में टेनिस के विकास और हैदराबाद को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

न्यूज ब्रीफ

अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी मोहित का दिल का दौरा पड़ने से निधन

जिंद। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी मोहित का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। मोहित हरियाणा के जिंद जिले के नंदगढ़ गांव से निकले हैं। उनके असामयिक निधन से परिवार ही नहीं गांव और कबड्डी जगत भी शोक में डूब गया है। मोहित ने हाल ही में अपनी चोट की सर्जरी भी करायी थी जिससे उबरकर वह वापसी की तैयारी कर रहे थे बचपन से ही मोहित ने गांव के पूर्व पहलवान प्रकाश के मार्गदर्शन में स्टेडियम में अभ्यास करना शुरू किया था। खेल के प्रति उनका जुनून इतना गहरा था कि कम उम्र से ही पढ़ाई और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के साथ-साथ कबड्डी का भी अभ्यास किया करते थे। अपने शानदार प्रदर्शन से वह वह एक बेहतरीन रेडर के रूप में टीम में जगह बनाने में सफल रहे। वह अपनी शानदार रेडिंग और मैच में दबाव की स्थिति में तत्काल फैसले लेने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हरियाणा और पंजाब के कई बड़े सर्कल कबड्डी टूर्नामेंटों में बेस्ट रेडर का खिताब भी जीता था। उनकी पहचान एक बेहतरीन रेडर के रूप में उभरकर सामने आई। स्थानीय और बड़े आयोजनों में उनकी रेड्स देखने लायक होती थीं और दर्शक उनकी कलात्मकता के कायल थे। मोहित ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई। दुबई, कनाडा और इंग्लैंड जैसे देशों में भी उन्होंने कबड्डी खेली और कई ट्राफियां जीतकर देश और अपने गांव का नाम रोशन किया। गत दिवस बुधवार की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका असमय निधन हो गया, जिसने सभी को सदमे में डाल दिया है। मोहित अविवाहित थे और उनसे पहले उनके परिवार में कोई भी पेशेवर पहलवान या खिलाड़ी नहीं था। उन्होंने अपनी मेहनत से परिवार में खेल की एक नई विरासत की नींव रखी थी। उनके निधन से नंदगढ़ गांव ने न सिर्फ एक होनहार खिलाड़ी खोया है, बल्कि कबड्डी जगत ने भी एक उभरते सितारे को खो दिया है।

भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं वाटसन

सिडनी। पूर्व आस्ट्रेलियाई आलराउंडर शेन वाटसन ने कहा है कि भारत उनके लिए दूसरे घर की तरह है क्योंकि यहां उनके देश से भी ज्यादा प्यार मिला है। वाटसन ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक आस्ट्रेलिया के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है पर इसके बाद भी भारत में उन्हें अधिक अपनापन और समर्थन मिला। उन्होंने भारतीय प्रशंसकों की सराहना करते हुए कहा कि भारत में उनके प्रदर्शन को लेकर उन्हें कम परखा गया और अधिक प्रोत्साहित किया गया, जबकि आस्ट्रेलिया में खराब प्रदर्शन के दौरान उन्हें कड़ी आलोचन झेलनी पड़ती थी। वाटसन ने कहा, यह वास्तव में मेरे लिए दूसरे घर जैसा लगता है। मैं भाग्यशाली था कि मैंने लंबे समय तक आस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेला, हालांकि मुझे भारत में हमेशा ज्यादा अपनापन महसूस हुआ। वाटसन के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने से भी भारत से भारत से उनके रिश्ते गहरे हुए हैं। इस आलराउंडर नेसाल 2008 में शुरू हुई इस लीग को अपने करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया, जहाँ उन्हें भारतीय प्रशंसकों से लगातार प्यार और समर्थन मिला। आईपीएल के जरिये उन्होंने राजस्थान रायल्स, रायल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी प्रमुख टीमों के लिए खेला और अब वह कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के साथ सहायक कोच के रूप में जुड़े हुए हैं।

जमशेदपुर एफसी के हटने से अब आईएसएल में उतरेंगी 13 टीमें : एआईएफएफ

नई दिल्ली। अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) ने कहा है कि जमशेदपुर एफसी के हटने के बाद अब इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के 2026-27 सत्र में कुल 13 क्लब ही शामिल रहेंगे। साथ ही कहा कि ये प्रतियोगिता होम-अवे आधार पर डबल राउंड-राबिन फार्मेट में खेली जाएगी। इस प्रारुप के तहत, सभी 13 टीमें लीग चरण में एक-दूसरे के खिलाफ दो बार खेलेगी। इसमें एक मुकाबला अपने घरेलू मैदान। वहीं दूसरा विरोधी टीम के मैदान पर खेला जाएगा। इससे प्रशंसकों को अपने पसंदीदा क्लबों के मुकाबले देखने के अधिक अवसर मिलेंगे। प्रत्येक क्लब के लीग चरण में कुल 24 मैच होंगे। क्लबों की संख्या के इस आधिकारिक निर्धारण से अब लीग से जुड़े व्यावसायिक समझौतों को अंतिम रूप देने और आगामी मैचों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को गति मिलेगी। लीग में 13 क्लबों की संख्या रहने की सबसे बड़ी वजहों में से एक जमशेदपुर एफसी का लीग से बाहर होना है। क्लब ने पिछले महीने ही घोषणा की थी कि वह 2026-27 सीजन से इंडियन सुपर लीग में हिस्सा नहीं लेगा। जमशेदपुर एफसी का संचालन करने वाली टाटा स्टील के स्वामित्व वाली कंपनी जमशेदपुर फुटबाल एंड स्पोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड(ने इस अप्रत्याशित फैसले की पुष्टि की थी।

दलीप ट्राफी फाइनल अब बेंगलुरु की जगह चेन्नई में खेला जाएगा

अधिक से अधिक दर्शकों को मिलेगा मैच देखने का अवसर

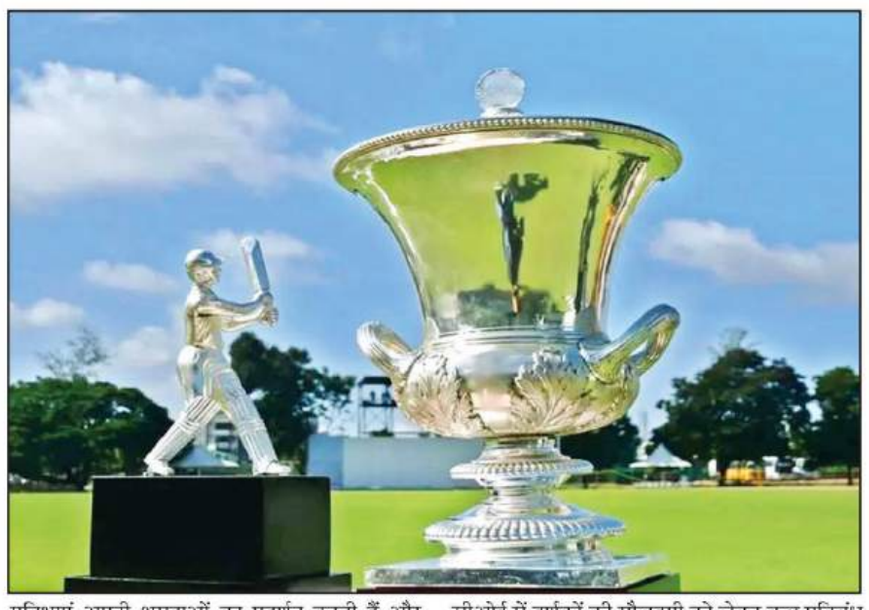

मुम्बई

घरेलू क्रिकेट के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट दलीप ट्राफी 2026-27 के फाइनल का मैच स्थल बदल दिया गया है। अब फाइनल बेंगलुरु के सेंटर आफ एक्सीलेंस (सीओई) की जगह पर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने कहा है कि यह फैसला अधिक से अधिक क्रिकेट प्रेमियों को इस अहम मुकाबले को स्टेडियम में बैठकर देखने का अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है। ये खिताबी मुकाबला 6 से 10 सितंबर तक खेल जाएगा।

माना जा रहा है कि बोर्ड ने ये कदम घरेलू क्रिकेट को प्रशंसकों के करीब लाने के लिए उठाया है। इसका कारण ये है कि सीओईमुख्य रूप से प्रशिक्षण और विकास पर केंद्रित है और इसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता सीमित है। वहीं विपरीत, चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम बड़े आयोजनों की मेजबानी करने और हजारों दर्शकों को समायोजित करने में सक्षम है। इस बदलाव से न केवल खिलाड़ियों को एक बड़े और अनुभवी मैदान पर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, बल्कि प्रशंसकों को भी घरेलू क्रिकेट की भव्यता और उत्साह का अनुभव करने का अवसर मिलेगा।

फाइनल का स्थल बदल गया है पर टूर्नामेंट के अन्य मुकाबले अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही बेंगलुरु के सीओई में ही खेले जाएंगे। दलीप ट्राफी का यह सत्र 23 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें शुरुआती दिन पूर्वी क्षेत्र का सामना पूर्वोत्तर क्षेत्र से होगा, जबकि उत्तरी क्षेत्र की भिड़ंत पश्चिम क्षेत्र से होगी। यह आयोजन भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा मंच है, इसमें युवा प्रतिभाएं अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती हैं और अनुभवी खिलाड़ी भी अपना प्रभाव दिखाते हैं।

गौरतब है कि दलीप ट्राफी भारतीय क्रिकेट कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है, जिसने दशकों से कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को तैयार किया है। 2026-27 सत्र में यह टूर्नामेंट अपने पारंपरिक क्षेत्रीय प्रारूप में लौट आया है, जिसमें कुल छह टीमें भाग ले रही हैं। इन टीमों में मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल हैं। यह प्रारूप क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और प्रतिभा की पहचान को बढ़ावा देता है, जो भारतीय क्रिकेट की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्थल परिवर्तन को लेकर कहा, दलीप ट्राफी हमारे घरेलू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है। इसमें हमेशा उच्च स्तर का क्रिकेट देखने को मिलता है और हम चाहते हैं कि प्रशंसकों को फाइनल मुकाबला स्टेडियम में देखने का मौका मिले। सैकिया ने कहा, सीओई में दर्शकों की मौजूदगी को लेकर कुछ प्रतिबंध हैं। इसलिए हमें लगा कि फाइनल को ऐसे मैदान पर कराया जाना सही होगा, जहां प्रशंसक आकर इस मुकाबले का हिस्सा बन सकें। यह बयान बीसीसीआई की उस दूरदृष्टि को दर्शाता है, जिसमें खेल के साथ-साथ उसके दर्शकों को भी समान महत्व दिया जाता है।

प्रशंसकों तक पहुंच बढ़ाने और घरेलू क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के लिए बीसीसीआई ने टूर्नामेंट के प्रसारण को भी विस्तार दिया है। दलीप ट्राफी के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, जिससे दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी कहीं से भी इन मुकाबलों का आनंद ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त, एक क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल और फाइनल का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिससे इन महत्वपूर्ण मैचों की पहुंच और भी व्यापक हो जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय घरेलू क्रिकेट का उत्साह और गुणवत्ता अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंच सके।

बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में लियोन को बाहर कर सकती है आस्ट्रेलिया, रेनशा की वापसी तय

मैकाय

आस्ट्रेलिया बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में आफ स्पिनर नाथन लियोन को बाहर कर तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरने पर विचार कर रही है। वहीं, बल्लेबाज मैथ्यू रेनशा की टीम में वापसी तय हो गई है।

आस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने क्रिकेट आस्ट्रेलिया के हवाले से कहा कि अंतिम एकादश पर फैसला शनिवार को टास से पहले मैदानी परिस्थितियों का निरीक्षण करने के बाद लिया जाएगा। टीम प्रबंधन ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में होने वाले पहले टेस्ट को देखते हुए स्काट बोलैंड को शामिल कर पूरी तरह तेज गेंदबाजी आक्रमण के साथ उतरने पर विचार कर रहा है।

कमिंस की कप्तानी में फिट रहने पर लियोन को आस्ट्रेलिया ने कभी टेस्ट टीम से बाहर नहीं किया है। हालांकि, पिछले साल गुलाबी गेंद से खेले गए टेस्ट में आस्ट्रेलिया दो बार बिना स्पिनर के सभी तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरा था।

रेनशा ने अपना आखिरी टेस्ट 2023 में भारत के खिलाफ खेला था। अब उनकी वापसी लगभग तय है। वह फिर से पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं। रेनशा ने 2016-17 में पाकिस्तान के खिलाफ 20 साल की उम्र में सलामी बल्लेबाज के तौर पर शतक लगाया था।

क्वींसलैंड के इस बल्लेबाज ने मैकाय में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दो शतक भी लगाए हैं। वह जेक वेदराल्ड की जगह टीम में आए हैं। वेदराल्ड को एक टेस्ट के बाद ही टीम से बाहर कर दिया गया है।

आस्ट्रेलिया टीम: पैट कमिंस (कप्तान), स्काट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मैथ्यू रेनशा, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर।

बांग्लादेश टीम: नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), मेहदी हसन मिराज (उपकप्तान), सौम्य सरकार, शादमान इस्लाम, तंजीद हसन तमीम, मोमिनुल हक शोहराब, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास, अमीते हसन, जाकेर अली अनिक, ताइजुल इस्लाम, तस्किन अहमद, हसन महमूद, सैयद खालिद अहमद, एबादत हुसैन चौधरी, मुस्फिक हसन, शरीफुल इस्लाम।

अक्टूबर-नवंबर में श्रीलंका और इंग्लैंड की मेजबानी करेगा पाकिस्तान

लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) देश में अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन के प्रयास कर रहा है। इसी के तहत ही पाकिस्तान टीम 9 अक्टूबर से 21 नवंबर तक अपने घर में श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमें के साथ त्रिकोणीय सीरीज खेलेगी। पीसीबी इससे देश में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी और लोकप्रियता को बढाना चाहता है। पीसीबी के अनुसार श्रीलंका की टीम 9 अक्टूबर को रावलपिंडी में करेगी, जहां वे पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में हिस्सा लेंगे। यह रोमांचक टी20 श्रृंखला 13 अक्टूबर तक चलेगी, जिससे प्रशंसकों को आक्रामक क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। इसके बाद इंग्लैंड की टीम भी इस कार्यक्रम में शामिल होगी। पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच एकदिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का आयोजन 18 से 31 अक्टूबर तक रावलपिंडी और लाहौर में किया जाएगा। यह लगातार दूसरा साल होगा जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्राफी 2025 से पहले अपने घर में एकदिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला की मेजबानी करेगा।

ब्रिटिश गायिका लारा राइट ने पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया, लोग हुए हैरान

हेडिंग्ले

यहां हेडिंग्ले में इंग्लैंड और मेहमान टीम पाकिस्तान के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच के शुरु होने से पहले एक अनौखा नजारा देखा गया। ब्रिटिश गायिका लारा राइट ने हजारों दर्शकों के सामने पाक का राष्ट्रगान गाया। इसके लिए एस गायिक ने बीते छह महीने से तैयारी करते हुए उर्दू तक सीखी थी। परंपरागत रूप से क्रिकेट मैचों में राष्ट्रगान बजना एक सामान्य प्रक्रिया है पर लारा की प्रस्तुति और इसके लिए किये अभ्यास से सभी हैरान रह गये।

गौरतलब है कि लौरा के लिए ये कोई पहली बार है जब उन्होंने किसी दूसरे देश के राष्ट्रगान को इतनी लगन से सीखा हो। इससे पहले साल 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की टेस्ट सीरीज के दौरान भी लारा राइट ने भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन भी गाया था। उस समय भी उन्होंने बंगाली सीखी थी। लारा ने माना है कि भारतीय राष्ट्रगान गाते समय वह शायद सबसे ज्यादा घबराई हुई थीं। वह बताती हैं कि शास्त्रीय संगीत सीखते समय इटालियन और जर्मन जैसी भाषाओं की बुनियादी समझ तो दी जाती है, लेकिन राष्ट्रगान गाते वक्त आपका सामना कई अलग-अलग भाषाओं से होता है। भारतीय राष्ट्रगान के लिए उन्होंने उच्चारण और शब्दों के उतार-चढ़ाव को समझने और उनके अर्थ को जानने के लिए इसे बार-बार सुना और कई ऐसे लोगों के साथ समय बिताया जो इसे बोलते थे। लारा राइट एक अंतरराष्ट्रीय कलाकार हैं, जो दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित आयोजनों में राष्ट्रगान गाने के लिए जानी जाती हैं। 15 साल की उम्र में उन्होंने कोरिसटर आफ द ईयर प्रतियोगिता जीती, जिसके बाद उन्होंने और लंदन के रायल कालेज आफ म्यूजिक से ओपेरा की पढ़ाई की। लारा शुरुआत से ही खेलों से जुड़ी रही हैं। वह इंग्लैंड रग्बी की पहली आधिकारिक एंथम सिंगर बनीं और उन्होंने ट्विकेनहैम, वेम्बली जैसे बड़े स्टेडियमों और रग्बी विश्व कप, एफए कप फाइनल, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स और लंदन में एनएफएल मैचों जैसे कई प्रमुख खेल आयोजनों में भी भाग लिया। क्रिकेट से भी उनका जुड़ाव कम नहीं है। 2016 में, उन्होंने हीरोज नामक गीत बनाया, जो इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम का पहला आधिकारिक एंथम बना।

मानव सुथार से बोले पुजारा, आईपीएल के लिए अपनी शैली न बदलें, प्रबंधन इस गेंदबाज को टेस्ट के लिए बचाये

मुम्बई

दिग्गज टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने उभरते हुए स्पिन आलराउंडर मानव सुथार की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा है कि उसे सीमित ओवरों के क्रिकेट खासकर आईपीएल को देखते हुए अपनी गेंदबाजी की मूल ताकत और शैली में बदलाव नहीं करना चाहिए। साथ ही कहा कि उसे टेस्ट के लिए बचाकर रखना चाहिए।

सुधार ने श्रीलंका के खिलाफ पहले ही टेस्ट में कुल 10 विकेट लिए थे। ये श्रीलंका की धरती पर किसी भारतीय गेंदबाज का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। वह श्रीलंका में एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले केवल तीसरे भारतीय गेंदबाज बने। उन्होंने विदेशी टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन का रिकार्ड भी अपने नाम किया, जो इससे पहले दिग्गज भारतीय स्पिनर बिशन सिंह बेदी के नाम था।

पुजारा ने कहा कि आजकल सभी युवा खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से छोटे फार्मेट और आईपीएल में खेलना चाहते हैं पर सुथार जैसे विशेष प्रतिभा वाले खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। उन्होंने टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं को भी सलाह दी है कि सुथार को टेस्ट क्रिकेट के लिए ही रखा जाये। पुजारा ने कहा, उसे बचाकर रखने करने की कोशिश करें। हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि युवा खिलाड़ी छोटे प्रारुप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत को उसे टेस्ट प्रारुप के लिए बचाकर रखना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सुथार को आईपीएल में खेलने का मौका मिलता है तो उन्हें जरूर खेलना चाहिए, लेकिन अपनी ताकत से समझौता नहीं करना चाहिए।

गौरतलब है कि मानव सुथार को गुजरात टाइटंस ने 2025 की मेगा नीलामी में उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपये पर खरीदा था। उन्होंने 2024 में आईपीएल में डेब्यू किया था पर सफल नहीं रहे। साल 2025 के सीजन में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, जबकि 2026 के सीजन में चार मैच खेलने के बाद उन्होंने तीन पारियों में गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने 34 के औसत और 11.33 की इकानमी रेट से केवल 2 विकेट लिए। उनका पहला विकेट आरसीबी के रजत पाटीदार का था और बाद में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के डेवाल्ड ब्रेविस को भी आउट किया। हालांकि, पंजाब किंग्स के सूर्यांश शेडगे के खिलाफ एक ओवर में 27 रन खर्च करने के बाद उन्हें उस सीजन में दोबारा मौका नहीं मिला। पुजारा की यह सलाह सुथार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें सफेद गेंद के क्रिकेट में अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए अपनी मूल शैली से हटना पड़ सकता है।

गाले टेस्ट में सुथार के शानदार प्रदर्शन के बीच, रविंद्र जडेजा की भूमिका एक सहयोगी गेंदबाज जैसी दिखी, और कुलदीप यादव को भी ज्यादा सफलता नहीं मिली। ऐसे में सुथार ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह को मजबूत कर लिया है। अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह सफेद गेंद के क्रिकेट में भी अपनी उपयोगिता साबित करें।

हेल्थ को ऐसे नुकसान पहुंचाता है मैदा...

मैदे का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि मैदे से बनीं चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है या नहीं। आज हम आपको मैदे के बारे में बताएंगे कि मैदा हमारी सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाता है। मैदे के कई साइड इफेक्ट होते हैं, जिनका हमें लंबे समय बाद पता चलता है। एक शोध से बात सामने आई है कि मैदे को सफेद रंग ब्लीच से दिया जाता है। इसके ज्यादा सेवन से हमारी सेहत खराब हो सकती है और कई तरह की परेशानियां भी हो सकती है। आइए जानते है मैदे से सेहत को होने वाले नुकसान...

डायबिटीज: मैदे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसके सेवन से शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगर आप भी मैदे का अधिक सेवन करते है तो संभल जाएं।

पेट की समस्या: मैदे में डाइट्री फाइबर बिल्कुल नहीं होता, इसलिए मैदे से बनी डिश का सेवन करने से ये पूरी तरह से पच नहीं पाता है। इसके सेवन से अक्सर कब्ज की समस्या हो जाती है।

फूड एलर्जी: मैदे में काफी मात्रा में ग्लूटन पाया जाता है जो खाने को लचीला बना कर उसको मुलायम टेक्सचर देता है और फूड एलर्जी का कारण बनता है।

हड्डियां कमजोर: मैदे में प्रोटीन ना होने से शरीर में एसिड बन जाता है, जो हड्डियों से कैल्शियम को कम करके उनको कमजोर कर देता हैं।

मोटापा: मैदा में स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे मोटापा बढ़ता है। यही नहीं इससे कोलेस्ट्रॉल स्तर भी बढ़ता है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो मैदे का कम सेवन करें।

आज ही छोड़े रात में लाइट जलाकर सोने की आदत

अगर आपको रात में लाइट जलाकर सोने की आदत है तो समय रहते ये आदत बदल डालिए क्योंकि एक रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि लाइट जलाकर सोने से आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हमारे शरीर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक सूरज और चांद की रोशनी से नियंत्रित होता रहता है जो कि कृत्रिम रोशनी के कारण गड़बड़ा रहा है। इसलिए कभी भी लाइट जलाकर नहीं सोना चाहिए। यदि हम रात को सोते समय लाइट जलाकर रखते है तो ये शरीर में कैंसर कोशिकाओं को एक्टिव करता है। एक अध्ययन से इस बात की पुष्टि हुई है कि सोने के समय अगर रोशनी हो तो ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका में 22 फीसदी का इजाफा होता है। लाइट जलाकर सोने से नींद में भी व्यवधान का सामना करना पड़ता है। आपने खुद ये बात महसूस की होगी कि जब भी फोन या लैपटॉप की लाइट जलती है आपकी नींद अपने आप टूट जाती है। सोते समय लाइट जलाकर रखना हमारे मूड पर तो असर डालता है। हमारे दिल को भी इससे नुकसान पहुंचता है। इससे हृदय सम्बंधी बीमारियां हमें धर दबोचती हैं। लाइट जलाकर रखने से हमारे ब्लडप्रेशर पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा ये हमारे दिमाग को भी नुकसान पहुंचाती हैं।

थायराइड के उपचार के लिए एक्यूप्रेशर

थायराइड हार्मोन चयापचय की दर को सही बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके ठीक से काम न करने से वजन का बढ़ना, थकान, हाथों और पैरों में ठंडापन,चिंता, बालों को झाड़ना जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। घबराइए नहीं एक्यूप्रेशर थेरेपी से इसका इलाज किया जा सकता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों खासकर हथेलियों और पैरों के तलवों के बिन्दुओं पर दबाव डालकर इलाज करने को एक्यूप्रेशर चिकित्साकहा जाता है।

मुंह और जीव के घाव में हरा धनिया सहायक

धनिया स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। हरे धनिया में विटामिन ए, सी, पोटैशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, कैरोटीन आयरन, फाइबर, जैसे पोषक तत्व काफी मात्रा में होते है, जो हर तरह के रोगों से शरीर को बचाते है। हरे धनिए में मौजूद एंटी-सेप्टिक गुण जीभ और मुंह के अंदर घाव होने से बचाता है। शरीर की आंतरिक और बाहरी जलन और पेट की एसिडिटी को दूर करता है।

क्या आप मांसपेशियों और चयापचय स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं? और बड़ी संख्या में स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाले प्राकृतिक पदार्थ की खोज कर रहे हैं? तो आपको मैलिक एसिड पर विचार करना चाहिए। यह स्वस्थ होने के साथ बहुत सारे लाभ प्रदान करता है।

मैलिक एसिड से दूर करें

क्रोनिक थकान सिंड्रोम...

मैलिक एसिड एक प्राकृतिक पदार्थ है, कि ज्यादातर फलों और सब्जियों के बीच पाया जाता है। जो कि सेब जैसे फलों के साथ जुड़ा होता है, और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए जाना जाता है। यह स्वास्थ्य समस्याएं फाइब्रोमयाल्जिया और क्रोनिक थकान सिंड्रोम के उपचार में लाभदायक होता है। इतना ही नहीं, अगर आप साफ, चमकदार और सॉफ्ट त्वचा चाहते हैं तो आपकी समस्या का हल निश्चित रूप से मैलिक एसिड है। आइए मैलिक एसिड के स्वास्थ्य और सौंदर्य लाभ के बारे में जानकारी लेते हैं।

एनर्जी बढ़ाए

हमें पूर्णरूप से जीने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अगर आपको भरपूर नींद लेने के बावजूद दिन भर एनर्जी महसूस नहीं होती या आप सुस्त महसूस करते हैं, तो समस्या आपके शरीर के साथ नहीं है बल्कि आपके खान-पान में हैं। आपके आहार में मैलिक एसिड का अभाव है। मैलिक एसिड के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एनर्जी के स्तर को बढ़ा देता है। यह प्रतिबंध चक्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जो आपके शरीर में एनर्जी में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। यह आपके शरीर में एनर्जी के स्तर के उत्पादन में सुधार करता है।

ओरल स्वच्छता के लिए बेस्ट

मैलिक एसिड आपके ओरल स्वच्छता के लिए अच्छा होता है। यह लार के उत्पादन को बढ़ा कर, मुंह में विषाक्त बैक्टीरिया के स्तर को कम करता है। इससे दांत साफ होते हैं और पीले निशान तेजी से कम होते हैं। इसके अलावा दांतों को सुरक्षा और मजबूती मिलती है। अक्सर, मैलिक एसिड वाणिज्यिक उत्पादों, माउथवॉश और टूथपेस्ट में मिलाया जाता है।

खूबसूरत त्वचा

मैलिक एसिड से भी त्वचा में अद्भुत निखार आता हैं। मैलिक एसिड त्वचा को लंबे समय तक सुंदर और स्वस्थ रखने में मददगार होता है। यह प्राकृतिक रूप से व्हाइटनिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है। जब आप इसे सीधा त्वचा पर लगाते है, तो यह त्वचा को एक्सफोलिएट और सॉफ्ट करता है, साथ ही एजिंग के निशान को भी कम करता है। साथ ही इसके इस्तेमाल से झुर्रियां दूर हो जाती है। इसके अलावा कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है जिससे मुंहासों के सभी लक्षण समाप्त हो जाते हैं।

दर्द कम करें

मैलिक एसिड शरीर के दर्द को कम करने के लिए भी जाना जाता है। हालांकि, इसके लंबे समय तक परिणाम देखने के लिए इसे आपको नियमित आधार पर लेना होगा। आमतौर पर शरीर के दर्द को कम करने के लिए 48 घंटे का समय पर्याप्त माना जाता है। अब आप जब भी गंभीर दर्द से परेशान होगें तो आपको पता है कि आपको क्या करना है।

कितना लें मैलिक एसिड

ज्यादातर अध्ययनों और शोधकर्ताओं के अनुसार, प्रतिदिन मैलिक एसिड की 1,200 से 1,800 मिलीग्राम तक राशि लेने की सिफारिश की जाती है। यह क्रोनिक थकान सिंड्रोम जैसी स्वास्थ्य की स्थिति के इलाज के लिए जाना जाता है। हालांकि मैलिक एसिड में विषाक्तता नहीं होती है, लेकिन इसके सेवन से कुछ लोगों का पेट खराब हो सकता है। अगर आपको नियमित आधार पर मैलिक एसिड लेने के लिए सिफारिश की है, तो प्रतिदिन 280 मिलीग्राम लेना, सबसे अच्छा रहता है।

अमृत समान है काले नमक का पानी...

आयुर्वेद के अनुसार काला नमक अपने आहार में शामिल करने से शरीर के कई रोग दूर हो सकते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, हाई बीपी, डिप्रेशन और पेट की तमाम बीमारियों से मुक्ती दिलाता है क्योंकि इसमें 80 प्रकार के खनिज शामिल हैं। अगर आप सुबह काला नमक और पानी मिला कर पीना शुरु कर दें तो आपको काफी स्वास्थ्य लाभ पहुंच सकता है। कुछ लोंगो को अभी पता नहीं है कि सादे नमक का बहुत ज्यादा प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है इसलिए अच्छा होगा कि आप उसे हटा कर काले नकम का सेवन कीजिए।

मोटापा घटाए: यह पाचन को दुरस्त कर के शरीर की कोशिकाओं तक पोषण पहुंचाता है, जिससे मोटापा कंट्रोल करने में मदद मिलती है। समुंद्री नमक छोड़ कर आपको इस नमक को अपने आहार में शामिल करना चाहिए।

जोड़ों के दर्द में आराम दिलाए: मासपेशियों के दर्द और जोड़ों के दर्द से यह नमक आराम दिलाता है। आपको एक कपड़े में 1 कप काला नमक डाल कर उसे बांध कर पोटली बनानी है। इसके बाद उसे किसी पैन में गरम करें और उससे जोड़ों की सिकाई करें। इसे दुबारा गरम कर के फिर से दिन में दो बार सिकाई करें।

आंत की गैस से छुटकारा दिलाए: अगर गैस से छुटकारा पाना है तो एक कॉपर का बरतन गैस पर चढाएं, फिर उसमें काला नमक डाल कर हल्का चलाएं और जब उसका रंग बदल जाए तब गैस बंद कर दें। फिर इसका आधा चम्मच ले कर एक गिलास पानी में मिक्स कर के पिएं।

सीने की जलन से मुक्ती: क्षारीय प्रकृति होने के नाते यह पेट में जा कर वहां बनने वाले एसिड को काटता है और सीने की जलन तथा एसिडिटी को ठीक करता है।

कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करे: काला नमक खाने से रक्त पतला होता है जिससे वह पूरे शरीर में आराम से पहुंचता है। ऐसे में आपका हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर ठीक होता है। हाइ बीपी है तो नमक की जगह पर खाएं यह मसल स्पैजम और क्रैंप में आराम दिलाए-काला नमक में पोटैशिमय होता है जो कि हमारी मासपेशियों को ठीक से काम करने में मदद करता है। इसलिये काले नमक को रोजाना खाने में शामिल करें जिससे मसल स्पैजम और क्रैंप ना हो।

शिशुओं के लिए भी अच्छा: काला नमक छोटे बच्चों के लिए सबसे अच्छा है। यह अपच और कफ की जमावट को सीने से हटाता है। अपने शिशु के भोजन में थोड़ा सा काला नमक रोजाना मिलाएं क्योंकि इससे उनका पेट भी ठीक रहेगा और कफ आदि से भी छुटकारा मिलेगा।

नींद लाने में लाभदायक: अपरिष्कृत नमक में मौजूदा खनिज हमारी तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। नमक, कोर्टिसोल और एड्रनलाईन, जैसे दो खतरनाक सट्रेस हार्मोन को कम करता है। इसलिए इससे रात को अच्छी नींद लाने में मदद मिलती है।

रूसी से मुक्ती दिलाए: अगर आपको रूसी और बाल झड़ने की समस्या है तो काला नमक और टमाटर का जूस हफ्ते में एक दिन सिर में लगाएं। यह रूसी को दूर करेगा और बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा।

शरीर करे डिटॉक्स: नमक में काफी खनिज होने की वजह से यह एंटीबैक्टीरियल का काम भी करता है। इसकी वजह से शरीर में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया का नाश होता है।

त्वचा की समस्या: नमक में मौजूद क्रोमियम एक्ने से लड़ता है और सल्फर से त्वचा साफ और कोमल बनती है। इसके अलावा नमक वाला पानी पीने से एग्जिमा और रैश की समस्या दूर होती है।

कैसे बनाएं काला नमक वाला पानी: एक गिलास गुनगुने पानी में आधा छोटा चम्मच काला नमक मिलाइए। फिर इसे चम्मच से मिक्स कीजिए और 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जब सारा नमक पानी में घुल जाए तब इसे पी जाइए एवं किसी भी उपचार को करने से पहले य अन्य किसी समस्या के लिए अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें।

LIFE-STYLE

छोटे-छोटे टिप्स कर सकते हैं जिंदगी में बड़े बदलाव

दाम्पत्य को खुशहाल बनाते बेडरूम में सुंदर चित्र

बेडरूम हमारे घर का बहुत ही खास हिस्सा होता है। कई बार बेडरूम में वास्तु दोष होने से उसका बुरा असर हमारे दांपत्य जीवन पर भी पड़ता है। वास्तु टिप्स का उपयोग हमारे बेडरूम में करें तो दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रह सकती है। ये वास्तु टिप्स इस प्रकार हैं...

दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए पलंग के सामने की दीवार पर सुंदर चित्र लगाने चाहिए। सुंदर चित्रों से मन में शांति की अनुभूति होती है और पलंग के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए। अगर पलंग के सामने दर्पण होगा तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। बेडरूम में पलंग हमेशा दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। सोते समय सिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो पश्चिम दिशा में पलंग रखना चाहिए। इस स्थिति में सोते समय मुंह पूर्व की ओर व सिरहाना पश्चिम की ओर रहना चाहिए। पूर्व की ओर व उत्तर की ओर मुंह करके सोना सुखदायक होता है। दक्षिण की ओर मुख करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण की ओर मुंह करके सोने से नींद नहीं आती है ।

दरवाजे से दूरी

बेडरूम में आपका बेड दरवाजे के पास नहीं होना चाहिए यदि ऐसा करेंगे तो चित्त में अशांति व व्याकुलता बनी रहेगी। बेडरूम में खिड़की अवश्य होना चाहिए। सुबह की किरणें बेडरूम में प्रवेश करने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है। कभी भी मुख्य द्वार की ओर पैर करके न सोएं।

बेड पर सीधे न पड़े प्रकाश

बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल कभी भी खिड़की के सामने न रखें, क्योंकि खिड़की से आने वाला प्रकाश परावर्तित होने के कारण परेशानी उत्पन्न करेगा। पलंग के सामने खिड़की न होकर ठोस दीवार होना चाहिए। बेडरूम में पलंग के दाईं ओर छोटी टेबल आवश्यक वस्तु रखने के लिए रख सकते हैं। बेडरूम में प्रकाश व्यवस्था ऐसी हो कि पलंग पर सीधा प्रकाश नहीं पड़े। प्रकाश सदैव पीछे या बांई ओर से आना चाहिए। मुख्य बेडरूम नैऋत्य (पश्चिम-दक्षिण) कोण में होना चाहिए। मुख्य बेडरूम वह होता है, जिसमें घर का मालिक सोता है। गलत दिशा में बेडरूम होने पर कमरे में राधा-कृष्ण का प्रेममय फोटो लगाएं। ऐसा करने पर कमरे के वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे।

रेसिपी

कॅरेमलाईस्ड बनानास्

सामग्री

2 बड़े पके हुए केले
2 टेबल-स्पून मक्खन
2 टेबल-स्पून ब्राउन शुगर
1/4 टी-स्पून दालचीनी पाउडर

विधि

प्रत्येक केले को छिलकर, 2 भाग टुकड़ो में काटकर, प्रत्येक टुकड़े को 2 लंबे भाग में काट लें। आपको कुल मिलाकर 8 टुकड़े प्राप्त होंगे। एक तरफ रख दें। एक चौड़े नॉन-स्टिक पैन में मक्खन गरम करें, ब्राउन शुगर डालकर, मध्यम आंच पर 1 से 2 मिनट या शक्कर के पिघलने तक, लगातार हिलाते हुए पका लें। केले डालकर अच्छी तरह मिला लें और मध्यम आंच पर 2 मिनट के लिए, बीच-बीच में हिलाते हुए पका लें। इन कॅरेमलाईस्ड केले के टुकड़ो को एक प्लेट में रखकर, दालचीनी पाउडर छिड़कर गुनगुने तापमान पर परोसें।

दही भल्ले

सामग्री

घोल के लिए: 250 ग्राम मूंग दाल, नमक स्वादअनुसार, **इमली की चटनी के लिए:** 1 कटोरी इमली का पानी, नमक स्वादअनुसार, 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, **अन्य साम्रगी:** 100 ग्राम दही, 4 चम्मच चीनी, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाऊडर, काला नमक स्वादअनुसार, **तलने के लिए:** तेल

विधि

दाल को पानी में 5-6 घंटे के लिए भिगो दीजिए, फिर उसे मिक्सी में पीस लें। पीसते समय पानी न मिलाएं। अब पैन में तेल गरम करें। पीसी हुई दाल के पेस्ट की पकौड़ी बनाकर फ्राई कर लें। तलने के बाद पकौड़ों को पेपर पर निकाल लें और हल्के गरम पानी में भिगो दें। अब दही को छानकर उसमें हल्का पानी मिलाएं। दही में चीनी,नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करें। अब पैन में इमली का पानी डालकर उबालें, फिर उसमें नमक, चीनी, लाला मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर मिलाकर चटनी तैयार करें। गरम पानी में भिगोई हुई पकौड़ियों को निकाल कर दही के साथ मिलाएं। ऊपर से इमली की चटनी डालें। काला नमक, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर छिड़क कर सज्ज करें।

एयरोस्पेस मैनेजमेंट में भविष्य की उड़ान

कुछ वर्षों के दौरान ग्लोबल कमर्शियल एयरोस्पेस सेक्टर महत्वपूर्ण विकास का साक्षी रहा है। एयरोस्पेस सेक्टर में हुए इस विकास की बदौलत ट्रेंड मैनेजर्स की जरूरत पैदा हुई है। इसे देखते हुए हाल ही में कनाडा की एचईसी मांट्रियाल ने एयरोस्पेस मैनेजमैंट में एमबीए डिग्री लॉन्च की है ताकि देश-विदेश में एयरोस्पेस सेक्टर में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके।

योग्याताएं जरूरी

एयरोस्पेस इंडस्ट्री में अक्सर मैनेजर्स की शुरुआत साइंटिफिक या टेक्निकल बैकग्राउंड से होती है, जिसके पश्चात वे टीम या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोजीशंस पर पहुंचते हैं, लेकिन इस कार्य के लिए उनमें कुछ विशिष्ट गुण, कौशल तथा योग्यताएं होनी जरूरी होती हैं। एयरोस्पेस मैनेजमैंट में एमबीए उन्हें वह कौशल देगा, जिसकी उन्हीं इस क्षेत्र में सफल होने के लिए जरूरत पड़ेगी। एयरोवर्ल्ड एमबीए नामक यह प्रोग्राम एक वर्षीय कोर्स है, जिसे एयरोस्पेस में महारत रखने वाले ईबीसी एयरोवर्ल्ड इंस्टीट्यूट के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ मिल कर करवाया जाएगा।

बेहतर कॅरियर की संभावनाएं

बोइंग के अनुसार अगले 20 वर्षों के दौरान नए विमानों में से आधे से अधिक की बिक्री चीन तथा भारत जैसे देशों में होगी। नए विमान बनाने में विलम्ब, अनिश्चितता, बड़ा पूंजी निवेश तथा लम्बे समय तक वसूली जैसी बातें जुड़ी होती हैं। ऐसे में एयरोस्पेस इंडस्ट्री को न केवल उच्च दक्षता व कुशलता सहित रणनीतिक दृष्टिकोण वाले इंजीनियर्स व वैज्ञानिक ही नहीं, अच्छी तरह प्रशिक्षित मैनेजर व लीडर्स भी चाहिए। इसलिए एयरोस्पेस मैंनेमेंट में एमबीए से आप इस क्षेत्र में भी कॅरियर की संभावनाएं तलाश सकते हैं। इसमें शुरुआती सैलरी 25 से 30 तक हो सकती है। इसे बाद तजुर्बा बढ़ने के साथ ही सैलरी में भी इजाफा होगा।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**